>

Title: Discussion on the Budget (General) for 2009-2010 and Excess Grants No. 16 and 22 in respect of Budget (General) for 2006-2007 (Discussion not concluded).

* Moved with the Recommendation of the President.

**14.17 hrs.**

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seventeen Minutes past*

*Fourteen of the Clock.*

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item Numbers 22 and 23 are to be taken up together. Motion moved:

> "That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2007, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 16 and 22."

* Moved with the recommendation of the President

MR. DEPUTY SPEAKER : Dr. Murli Manohar Joshi

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी):** उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस सरकार की दूसरी पारी के पहले बजट के बारे में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है और समय दिया है। मेरे सामने माननीय वित्त मंत्री जी विराजमान हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण में कुछ ऐसे लक्ष्य रखे हैं जो यदि पूरे हो जाएं, तो सारे देश को बहुत प्रसन्नता होगी और मैं प्रभु से यह कामना करता हूं कि उन्हें शक्ति दे कि वह इन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो सकें। मुझे यह आशंका है कि जितने महान लक्ष्य उन्होंने रखे हैं, वे पूरे हो सकेंगे या नहीं।

महोदय, बजट भाषण में लक्ष्य घोषित करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको पूरा करना और उसको पूरा करने के लिए साधन जुटाना और उसके साथ-साथ एक इच्छा शक्ति को प्रकट करना, एक प्रबंधन को सामने लाना, आर्थिक और वित्तीय साधनों को जुटाना, यह बहुत कठिन काम है। आज की परिस्थिति में जो लक्ष्य उन्होंने रखे हैं, उनकी तरफ वे सफलता के साथ बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि देश को बहुत प्रसन्नता होगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य बनाने के बाद शायद वह अब यह सोचें कि वे कुछ ज्यादा कह गए हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए, गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, किसानों और खेती को उसकी वास्तविक स्थिति जो इस देश में कभी थी, वहां तक पहुंचाने के लिए जहां कहीं हमारी और हमारे राज्यों की सरकारों की सहायता की जरूरत होगी, हम उसके लिए तैयार हैं।

आपने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि नई सरकार सन् 2009 और 2010 की अपनी जो नीतियां बनाएगी, उनके कुछ विशेष और ऐसे लक्ष्य होंगे जिन्हें आपने गिनाया है। आपने 8 या 10 लक्ष्य गिनाए हैं। उनमें से एक लक्ष्य है -

> "sustain a growth rate of at least 9 per cent per annum over an extended period of time."

इसके साथ-साथ आपने और जो बातें लिखी हैं, उनका एक महत्वपूर्ण पैरा आपको बताता हूं -

> "ensure that Indian agriculture continues to grow at an annual rate of 4 per cent."

यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और यदि इसे चार प्रतिशत कंटीन्यू करें, इसे आप इनश्योर करें, अगर आप इस बजट के माध्यम से उसे कर सकें, तो मैं समझता हूं कि आप इस देश में चमत्कार कर देंगे।

मेरे सामने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो अप्रैल, 2008 में छपी। उसमें कहा गया है -

> "The slow growth of agriculture has been explicitly noted as a matter of concern in the Approach Paper to the 11th Plan and accelerating the rate of growth of agricultural production is seen as central to a more inclusive growth, if not growth *per se*."

इनक्लूसिव ग्रोथ आपके इस बजट का एक मुख्य केन्द्र बिन्दु रहा है। आगे चलकर रिपोर्ट कहती है -

> "Taking output growth first, we find that even close to four decades since the Green Revolution there is no permanent rise in the rate of growth. Together with the data for cereal, since 1991 we are able to see that it is the slowing of output growth in this decade that depresses the rate of growth from 1967 to 2003. To sum up then, there is an across the board slowing of output and yield growth since 1991 for the two main groups in Indian crop agriculture. For all crops there is slowing of growth in area, production and yield."

There is a slowing of growth in area, production and yield. This is very serious.

It further says:

> "The period since 1991, that is when the reforms began, now emerges as a kind of watershed in time when growth in Indian agriculture, resurgent from the middle 1960s, was arrested. Concerns of livelihood and food consumption arise naturally from the recent record of agricultural growth."

आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर इम्प्लॉयमैंट निर्भर करता है, उस पर देश का सारा आर्थिक विकास निर्भर करता है क्योंकि 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है।

उपाध्यक्ष जी, मेरे सामने एक और तस्वीर है जो बहुत चिन्ताजनक है। वह यह है कि हमारे देश की जनसंख्या जैसे-जैसे बढ़ी है, वैसे-वैसे मैं देख रहा हूं कि हमारा अन्न का उत्पादन घटा है और अन्न उत्पादन के लिए जो कृषि क्षेत्र था, कृर्षित क्षेत्र था, वह भी घट गया है। इसके साथ-साथ अन्न की उत्पादकता भी घट गई है यानी प्रति हैक्टेयर जितना उत्पन्न होना चाहिए, उतना उत्पन्न नहीं हो रहा है। हमारे देश में कृषि के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है, वह उपलब्ध नहीं है, वह निरंतर घट रही है। हमारे पास उसके आंकड़े हैं। हमारे पास सन् 1971 में 1,24,316 हजार हैक्टेयर उपलब्ध था और आज यह 1,23,710 हजार हैक्टेयर रह गया है। यह फूडग्रेन्स के अंदर ही घटा है। इसके अतिरिक्त जो भूमि है, जिसमें अन्न के अलावा और चीजें पैदा होती हैं, वह क्षेत्र भी घट गया है। इसी तरह यील्ड घट गई है और फूडग्रेन प्रोडक्शन जो एक बार हमारे देश में 202 किलोग्राम पर कैपिटा, पर ईयर हो गया था, वह फिर से घटकर 191 किलोग्राम पर कैपिटा पर ईयर हो गया है।

इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा को छोड़कर बाकी सब जगह अन्न उत्पादन घटा है। केवल पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जिसमें अन्न उत्पादन अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन बाकी सब जगह घट गया है। बिहार में 134 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से घटकर 91 किलोग्राम रह गया है। इसमें झारखंड भी शामिल है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 254 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हुआ करता था, वह घटकर 210 किलोग्राम रह गया है। इसमें उत्तरांचल भी शामिल है। तमिलनाडु में सिर्फ 104 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उत्पादन हो रहा है और केरल में केवल 19 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की ऐवेलेबिलिटी है। खेती की यह जो स्थिति है, उसी तरह से अन्न के लिए उपलब्ध भूमि और पैदावार की स्थिति है, यह बहुत चिंताजनक है। आप कहते हैं कि इसे आप चार प्रतिशत तक ले जायेंगे। आप इसे कैसे ले जायेंगे? मैं आपका एलोकेशन देखता हूं, तो इस बार एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के लिए 10629 करोड़ रुपये है, जो सारे खर्चे का केवल एक प्रतिशत है। आपने जो 10 लाख कुछ हजार करोड़ रुपये रखे हैं, उसका केवल एक प्रतिशत भाग आप कृषि पर खर्च कर रहे हैं जबकि आपका लक्ष्य उसे चार प्रतिशत तक की ग्रोथ तक ले जाने का है। दूसरी तरफ हम यह देख रहे हैं कि किसानों की आमदनी किस तरह से घट रही है और आज उसकी क्या हालत है? एनएसएसओ के वर्ष 2003-04 में जो आंकड़े थे, उसके तहत किसानों की आमदनी 2115 रुपया प्रति परिवार प्रति मास थी। आजकल घर में काम करने के लिए हमारे जो भाई बहन आते हैं, उनको भी तीन हजार रुपये से कम नहीं मिलता। दिल्ली में तो चार, साढ़े चार हजार रुपये तक मिलते हैं, लेकिन किसानों की आमदनी औसत देश भर में 2115 रुपया प्रति परिवार प्रति मास थी। यह आमदनी प्रति व्यक्ति न होकर प्रति परिवार है।

कल्याण सिंह जी, यू.पी. में यह आमदनी 1630 रुपये प्रति परिवार है। जम्मू-कश्मीर में सबसे अधिक आमदनी 5500 रुपये है। वहां बागवानी की वजह से यह आमदनी ज्यादा है। पंजाब में तीन हजार रुपये है। उसके बाद केरल है। अगर यह स्थिति किसानों की आमदनी की है, अगर यह स्थिति भूमि पर काम करने वाले लोगों की है, तो स्वाभाविक है कि लोग छोड़कर चले जायेंगे और आपका एनएसएसओ 2005 का कहना है कि

> "About 41 per cent Indian farmers have expressed their willingness to opt out of the agriculture. In Punjab too nearly 37 per cent farmers expressed their willingness to leave agriculture. About two lakh small and marginal farmers in Punjab have already been pushed away from farming during 1990-2001, according to a recent survey."

अब अगर आप यह स्थिति देखें, तो इसे चार परसेंट ग्रोथ तक ले जाना, वास्तव में आपने बहत बड़ा लक्ष्य लिया है। अगर आप इसे पूरा करेंगे, तो देशवासी

आपका बहुत गुणगान करेंगे। हम इसमें आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं, मगर हम रास्ता जानना चाहते हैं कि इसे आप कैसे करेंगे? मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, जिन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहेंगे, तो मैं दे सकता हूं। वैसे सब आंकड़े आपकी ही सरकार के दिये हुए हैं। हालत यह है कि अभी उस दिन सदन में हमारे एक सम्मानित सदस्य ने बताया था कि चार-पांच हजार किसान इच्छा मृत्यु के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें मरने की इजाजत दे दी जाये।

Janata Dal (United) Legislator from Chhatarpur, Shri Radhakishan Kishore had said that failure of the successive Governments to address the issue of water scarcity in the area which had been declared drought prone by the Centre in 1974 was responsible for this.

आप पानी के लिए क्या करेंगे? कृषि को ठीक करने के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे सामने आपके पुराने वित्त मंत्री माननीय श्री चिदम्बरम जी, उन्होंने इससे पहले की सरकार में जो पहला सामान्य बजट पेश किया था, उसका भाषण है। उसमें वे कहते हैं कि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के पांच उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विविधीकरण के माध्यम से कृषि विकास में तेजी लाना है।

वह आगे कहते हैं:

"अब मैं अपने एक बड़े स्वप्न की चर्चा करता हूं। जल किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा है। हमें चेतावनी दी गयी है कि 21वीं शताब्दी में विश्व को जिस सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, वह जल का संकट होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि एक मिलियन से भी अधिक ऐसी संरचनाएं हैं, जिनमें से लगभग 5 लाख संरचनाओं का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। उनमें से बहुत-सी संरचनाओं का उपयोग ही नहीं किया जाता है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कृषि से जुड़े सभी जल-निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनःस्थापना के लिए एक बड़ी योजना आरम्भ की जाए। "

यह योजना आरंभ करने की घोषणा की गयी, पांच साल पूरे हो गए। मैं नहीं जानता कि इन पांच लाख में से कितने कुएं, कितने तालाबों, कितनी झीलों का पुनर्वास हुआ। अगर कृषि के लिए यही दृष्टिकोण रहेगा तो यह विकास दर चार प्रतिशत नहीं, मुझे शक है कि यह 1.6 प्रतिशत से भी कम होकर कहीं एक प्रतिशत न रह जाए। उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था।

फिर कहा गया कि दूध और दुग्ध उत्पादों में आनन्द मॉडल बहुत अधिक सफल रहा है। सरकार का एक बागवानी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। यह मामला भी कृषि से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं, इसका लक्ष्य बागवानी उत्पादन को 150 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से दोगुना करके वर्ष 2011-2012 तक 300 मिलियन टन करना है। हम इस समय वर्ष 2009-10 में हैं। मैं नहीं जानता हूं कि कृषि क्षेत्र में, बागवानी में या डेरी फार्मिंग में केन्द्रीय सरकार की किसी भी योजना से कोई प्रगति हुई हो और वह इतनी पर्याप्त हो कि हमारे कृषि उत्पादन को चार प्रतिशत तक पहुंचा सके। इसी तरह से कृषि कारोबार को बढ़ाने के लिए एक संगठन की स्थापना करने की बात कही गयी थी, उसका कहीं पर जिक्र नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि कृषि की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक सिंचाई है, पानी है, लेकिन उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। नदियां सूख रही हैं, ग्लेशियर्स सूख रहे हैं, जलस्तर भूमि के नीचे बहुत दूर तक जा चुका है, आप कैसे कृषि को उबारेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हवा से तो कृषि नहीं होगी। यहां बहुत से लोग हैं जो कृषि करते हैं, पानी जमीन के बाद मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है। जमीन घट रही है, पानी घट रहा है, मगर कृषि में विकास दर को बढ़ाने की बात की जा रही है। यह विसंगति मेरी समझ में नहीं आ रही है।

कृषि के ऊपर जिस एक अन्य बात का घातक दुष्परिणाम होने वाला है वह जलवायु परिवर्तन है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर कभी माननीय वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार जलवायु परिवर्तन के मामले में इस सदन में कोई गंभीर बहस, इस आशय से ही करे कि उसका असर इस देश की खेती पर, इस देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर, उद्योगों पर, इस देश के रोजगार पर क्या होगा। यह कहा जाता है कि बहुत दिनों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जा रहा है कि सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। मैं भी यह कहना चाहूंगा कि पेयजल हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और जीवन के अधिकार के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल मिलने का अधिकार उसको दिया जाना चाहिए। यह एक लम्बी बात होगी, लेकिन अभी जो ग्लोबल ह्युमेनिटेरियन फोरम की रिपोर्ट है, जो 29 मई को श्री कोफी अन्नान जी द्वारा प्रकाशित हुई है, उसमें कहा गया है :

"Climate change is killing about 3,15,000 people a year through hunger, sickness and weather disaster, and the annual death toll is expected to rise to half-a-million by 2030. "

अगर खेती में अनाज का उत्पादन कम होगा तो भूख बढ़ेगी। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया के 100 करोड़ भूखों में से 25 करोड़ से अधिक इस देश में निवास करते हैं। अगर कृषि नहीं बढ़ी तो यह भूख कैसे मिटेगी? आप इस देश को कैसे आगे ले जाएंगे? अगर जलवायु परिवर्तन के बारे में गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो फिर यह प्रश्न कैसे हल होगा? क्या हिन्दुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा भूखों, सबसे ज्यादा बेघरों का, सबसे ज्यादा कुपोषित लोगों का और सबसे ज्यादा बीमार लोगों का देश बनेगा? कृषि के माध्यम से ही आप लोगों को भोजन दे सकते हैं, बच्चों को भोजन दे सकते हैं, बच्चों की माताओं को भोजन दे सकते हैं। अगर देश में स्वस्थ माताएं और स्वस्थ बच्चे होंगे तभी इस देश के उत्पादन में, इस देश की इकोनॉमिक एक्टीविटीज में आपको वृद्धि मिलेगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो आंकड़े हैं, उसमें स्टिंटेड ग्रोथ बढ़ रही है।

मेंटली रिटार्डेड बच्चों की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि वे कुपोषित हैं। अगर बच्चा अंडरवेट है, उसे और उसकी मां को पोषण नहीं मिला है, तो वह बच्चा देश के लिए उपयोगी नागरिक नहीं हो सकता, वह देश पर भार होगा। वैसे भी इस देश में काफी मात्रा में भूख से पीड़ित, बेरोजगारी से ग्रसित और बीमारियों से परेशान जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्लाइमेट चैंज के बारे में, चाहे कृषि के बारे में हो या औषधियों की तरफ से हो या जल के कारण से हो, उस पर जितना बल आपके बजट में दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। उसका उल्लेख है, लेकिन उस बारे में गम्भीरता नहीं है। आपने कृषि विकास दर चार प्रतिशत रखने की बात कही है, तो इस तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल इकॉनोमिक प्रोसेपेक्ट्स 2009 के लिए विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है, वह कहती है कि हम सिर्फ सब-सहारन कंट्रीज से आगे हैं, बाकी दुनिया में हम गरीबी के मामले में सबसे पीछे हैं। भारत में 12 मिलियन नए रोजगार पैदा करने का उद्देश्य दर्शाया गया है, जो गरीबी मिटाने के लिए आपके कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण चीज है। मैं जानना चाहता हूं कि गरीबी मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? गरीबी की परिभाषा क्या है, पावर्टी लाइन किसे कहा जाएगा, क्या जो विश्व बैंक की परिभाषा है, वह मानी जाएगी या जो एनएसएस जो परिभाषित करता है, वह मानी जाएगी, जबकि उसकी भी दो-दो परिभाषाएं हैं या योजना आयोग जो कहे, उसे मानेंगे या कोई राज्य सरकार अपनी परिभाषा कर ले तो उसे मानेंगे या कैलोरी इनटेक को हम गरीबी की परिभाषा मानेंगे या आर्थिक वह कितना खर्च करता है उसे मानेंगे? सिर्फ खाने पर कितना खर्च करता है उसे मानेंगे, दवाई-कपड़े और मकान पर खर्चा भी शामिल होगा या नही, ये सब सवाल आपके बजट में कहीं आते नहीं हैं या नहीं? हमें यह बताया गया है कि हिन्दुस्तान में आपके जो आंकड़े आते हैं, उनसे लगता है कि कुछ गरीबी घटाई गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पड़ौस के देशों में गरीबी तेजी से घटी है। उसे घटाने में बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे आगे हैं, चीन तो बहुत आगे है। ये आंकड़े कहते हैं कि 1990 में हमारे यहां 51.3 प्रतिशत एक्सट्रीम पावर्टी के लेवल पर थे, जो 2005 में घटकर 41.6 प्रतिशत हो गए। लेकिन इसी दौरान चीन में यह स्थिति 60 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत तक हो गई। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर दो पड़ौसी देशों के बीच में, जिनकी समस्या लगभग समान है, जो लगभग एक ही समय आजाद हुए हों, वहां अगर प्रतिस्पर्धा में वह आगे बढ़ रहा हो और इस मामले में हम पिछड़ जाएं, तो वित्त मंत्री जी मुझे क्षमा करें, हम फौज का भी अच्छी तरह से निर्माण नहीं कर सकेंगे, शिक्षा का भी नहीं कर सकेंगे। इतनी बड़ी संख्या देश में गरीबों की रहेगी, तो यह चिंता का विषय हमारे लिए होगा। हम जानते हैं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे इस देश के अंदर आंतरिक सामाजिक असंतोष बढ़ेगा। देश में इससे डिवाइसिव टेंडेंसीज़ बढ़ेंगी। यह इन्क्लूसिव ग्रोथ के खिलाफ जा रहा है, यह डिवाइसिव ग्रोथ है। अगर 50 प्रतिशत लोग इसी तरह देश में पड़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल बात होगी। अगर मैं अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के बारे में जिक्र करूं, तब तो स्थिति और भी भयावह है। रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अनुसार 77 प्रतिशत लोग 20 रुपए प्रतिदिन पर गुजर करते हैं। यह बहुत भयावह स्थिति है। इस सारे असंगठित क्षेत्र के लिए इस बजट में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहेंगे कि ग्रामीण रोजगार योजना की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं और उससे हम नए रोजगार पैदा करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका जो परिणाम है, वह बहुत ही निराशाजनक है।

अभी आपके मंत्री महोदय ने बयान दिया है कि NRGEA is not working properly. वे कहते हैं कि 100 दिन का रोजगार कहीं भी नहीं दिया जा सका है, ज्यादातर राज्यों में 40 दिन, 42 दिन, 43 दिन से अधिक रोजगार नहीं मिला है। बहुत अधिक मात्रा में पैसे का क्षरण हुआ है और इनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। इनसे स्थाई रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। यह अब एक तरह से अनएम्प्लाएमेंट डोल है और उसमें काम नहीं हो रहा है। हम इस योजना में पैसा लगा रहे हैं, मुझे आपकी सद्-इच्छा पर मुझे कोई संदेह नहीं है आप जरूर चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए ही क्यों न हो, 100 दिनों के लिए ही क्यों न हो लोगों को काम मिलना चाहिए। वैसे तो आपने इसमें एक परिवर्तन कर दिया, जहां पहले घोषणा थी कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, अब शायद उसमें केवल प्रति-परिवार बीपीएल में एक ही व्यक्ति को रोजगार मिलता है। सवाल यह है कि यदि यह भी 42-43 दिन का ही है तो बाकी समय का क्या है? रिपोर्ट एक यह भी है कि बजाए इसके कि इससे वहां लोगों को रोजगार मिले, कुछ किसानों के सामने समस्या आ गयी क्योंकि वे इस रेट के ऊपर देने में असमर्थ हैं। अच्छा हो अगर आप इस योजना के दूसरे पहलू पर भी विचार करें। क्या आप एम्प्लाएमेंट सब्सिडी एम्प्लायर को दे सकते हैं, जो एम्प्लाएमेंट जैनरेट करे। जो जितना ज्यादा एम्प्लाएमेंट जैनरेट करे, अगर उसे कुछ नुकसान या घाटा है तो उस सब्सिडी से वहां भी घाटा पूरा किया जाएगा, ताकि उसे स्थाई रोजगार मिल सके। कोई संस्थान है, कोई इकोनॉमिक एक्टीविटी करने वाले लोग हैं, आप उनके लिए कोई नियम बना सकते हैं, कोई कसौटी बना सकते हैं लेकिन जब तक स्थाई रोजगार नहीं बनेगा, तब तक काम नहीं होगा। इस पहलू पर विचार करें, इस योजना का एक अंग यह भी हो सकता है कि एक परमानेंट रोजगार देने के लिए इस योजना के एक हिस्से का उपयोग किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर एग्रो-इंडस्ट्रीज का विस्तार किया जा सकता है और उनके एम्प्लायर्स को इस नीति से काम दिया जा सकता है। गांव में ऐसे बहुत से काम है जो भट्टे के, ईंट के, लकड़ी के, खेल-खिलौनों के, आचार-मुरब्बों के हैं। एग्रो-इंडस्ट्री से बहुत सा एम्प्लायमेंट जैनरेट हो सकता है। आप अगर इस तरफ भी सोचें, योजना का एक हिस्सा इस तरफ भी लाएं तो शायद कुछ लोगों को स्थाई रुप से रोजगार मिलेगा और उनको काम करने में सुविधा होगी। लेकिन यह चिंताजनक बात है कि जो परिणाम आ रहा है वह ज्यादा उत्साहपूर्ण नहीं है।

सारी दुनिया में गरीबी से लड़ने के लिए बड़े-बड़े देश ऊंची-ऊंची बातें करते हैं लेकिन उनकी नीयत हमें साफ नज़र नहीं आती है। मैं समझता हूं कि ऐसा हमारे देश में नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हम लोग सही मायने में गरीबी को दूर करना चाहते हैं। अगर इस मामले में कहीं पर भी हमारी जरूरत है, लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, उनको दरिद्रता के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए तो हमारे नेता यहां बैठे हुए हैं और मैं बिल्कुल निसंकोच कह सकता हूं कि हम इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। यह जानकर बहुत दुःख होता है जब कोई कहता है कि आप सिर्फ सब-सहारन कंट्रीज से ही आगे हैं, बाकी सबसे पीछे हैं।

सवाल यह आता है कि अनाज के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि यह कैसी विडम्बना है कि सरकार कह रही है कि मुद्रा-विस्तार नैगेटिव हो गया, लेकिन खाद्यान्न और सब्जी के दाम निरंतर ऊंचे होते जा रहे हैं। अगर ये बढ़ा तो इंफ्लेशन के इंडैक्स के बारे में बड़ी फड़फड़ाहट है कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का भयानक अंतर क्यों है? मुझे मालूम है कि आप भी इससे चिंतित हैं और प्रधान मंत्री जी भी इससे चिंतित हैं। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का पुनर्निर्धारण होना चाहिए और यह वस्तुस्थिति को सही बताए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि बजट में इस तरफ ध्यान देने की बात नहीं कही गयी है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का यह भेद और उनका रेशनलाइजेशन, उनको ठीक ढंग से निर्धारण करने

की पद्धति विकसित की जानी चाहिए और यह जितनी जल्दी की जाए, उतना अच्छा है।

अगर खाद्यान्नों के दाम और बाकी दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ते गये तो फिर आप कितना भी पैसा इन योजनाओं में लगाएंगे, वह बेकार हो जाएगा, वह उत्पादक श्रम के लिए नहीं जाएगा, केवल आहार और दिनोंदिन चीजों की पूर्ति में लग जाएगा।

मेरा एक सुझाव है कि आप लक्ष्य निर्धारित करें कि हम हिंदुस्तान को भूख से मुक्त करें। भूख मुक्त हिंदुस्तान, कर्ज मुक्त किसान, यह है सम्पन्न भारत की पहचान। हिंदुस्तान में कोई भूखा न रहे। हिंदुस्तान में कोई किसान कर्जदार न रहे, प्राइवेट बैंक का भी नहीं और महाजन का भी नहीं। किसान को कर्ज लेने की जरूरत ही न पड़े। वह खेती में इनवेस्ट कर सके, उसकी इतनी आमदनी हो। जीरो हंगर - हम जीरो टालरेंस फार टेरेरिज्म करते हैं, जीरो टोलरेंस फार सो मैनी थिंग्स करते हैं, करप्शन के लिए करते हैं, क्या हम देश के सामने जीरो हंगर का लक्ष्य नहीं रख सकते हैं? तब आप चार प्रतिशत ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोगों को उत्साहित करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह बड़ा लक्ष्य है कि इस देश में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए। 25 करोड़ लोग इस देश में रोज भूखे सोएं, यह किसी भी सरकार के लिए शोभनीय नहीं है। आपने कौटिल्य का उदाहरण दिया था, थोड़ा बहुत कौटिल्य मैंने भी पढ़ा है, उसने कहा है कि राजा का बहुत बड़ा दायित्व देश में अनाज पैदा करने का है। आपकी इजाजत हो, तो मैं चार लाइन पढ़ना चाहता हूं -

> "Salutation to God Prajapati Kasyapa. Let the crops flourish always. Let the Goddess reside in the seeds and the grains."

अन्नं ब्रह्मः - इस रूप में अन्न पैदा हो, सारी फसल हमेशा लहलहाती रहे। शस्य श्यामला भूमि बनी रहे। वंदे मातरम, हम लोग यहां गाते हैं। उसी प्रकार की शस्य श्यामला भूमि वित्त मंत्री जी बनाइए। हम आपका साथ देंगे। आप यह लक्ष्य रखें, तो शायद देश को प्रेरित कर सकें। खाली बजट के आंकड़े रखने से बात नहीं बनती है, balancing of the expenditure and revenue, यह तो चार्टर्ड एकाउंटेंट भी कर लेता है, उसके लिए प्रणब मुखर्जी की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इच्छाशक्ति और लक्ष्य की है। यदि आप हिन्दुस्तान को हंगर फ्री बनाएंगे, तो वह एक बड़ी बात होगी।

महोदय, मंत्री जी ने सोशल सिक्योरिटी और हेल्थकेयर का एक लक्ष्य रखा है। यह बहुत अच्छी बात है। देश का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, लेकिन वह कैसे होगा? हिन्दुस्तान में सोशल सिक्योरिटी की हालत यह है कि 0.25 प्रतिशत भी उसमें नहीं दे रहे हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में आपका प्लान का खर्च 18380 करोड़ रूपये है, जो कि पूरे प्लान आउट ले का 0.25 प्रतिशत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इस देश के लोगों को हेल्थकेयर कैसे दे सकते हैं? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में फैमिली प्लानिंग के नाम से जो चीजें चलती हैं, उस पर खर्चे हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसे बदलने की जरूरत है। मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी है, जिससे मुझे चिंता हुई है। इस देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देश में धीरे-धीरे बिगड़ रहा है। विश्व बैंक और डब्ल्यूएचओ के आंकड़े आपके पास हैं। मैं उसे कहना नहीं चाहता हूं और अच्छा भी नहीं लगता है। हमारे देश में इन्फेन्ट मोर्टेनेटी रेट इस समय क्या है? यह कहते हुए शर्म आती है कि प्रेगनेंट मदर्स की मृत्यु दर अभी घट नहीं पायी है। शर्म आती है, जब हम यह देखते हैं कि प्रीनेटल और पोस्ट-नेटल केयर नहीं है। हम देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में माताओं के लिए कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। मूल रूप से जहां से मानव संसाधन शुरू होता है, वहां यदि चिकित्सा ठीक नहीं है, तो चिंता होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैकसीन्स की कमी हो गई है। दिसम्बर 2008, "A team of Health Ministry officials toured 13 States to review the National Rural Health Mission. They found, among other things, hospitals in Bihar did not have vaccines for Diphtheria, Woofing Cough and Tetanus." यह वैकसीन्स बिहार सरकार नहीं बनाती है। यदि वह बनाती होती तो हम उन्हें दोष दे सकते थे। यह सरकारी कम्पनियों में बनते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह बंद कर दी गई और अब प्राइवेट कम्पनियों को वैकसीन्स बनाने का काम दे दिया गया है।

आज नतीजा यह है कि The review also reported shortages in Assam where measles vaccine was not available; in Chhattisgarh measles vaccine was in very short supply; in Kerala Diphtheria and Tetanus vaccines were in short supply in the primary healthcare centres in Thiruvananthapuram and in Uttar Pradesh DPT and TT were not there. यह रिपोर्ट में लिखा है कि कितने बच्चे इसके अभाव में असमय में ही काल के गर्त में चले गये। गांवों में जहां अधिकतर पोलियो का तो बहुत जोर से प्रचार करते रहे हैं, कुछ काम होता भी रहा है, लेकिन टिटेनस हो जाए और एक स्थान पर जहां टिटेनस का इलाज होता है, उसे बच्चा मुर्दाघर कहा जाता है क्योंकि वहां कोई वैक्सीन नहीं है। डिप्थीरिया की वैक्सीन नहीं है, डीसीजी की वैक्सीन नहीं है, टी.बी. फैल जाए तो क्या होगा? एक तरफ हम मलेरिया और कालाजार की चिंता करते हैं लेकिन उसकी रिसर्च के बारे में हमारा कोई ध्यान नहीं है। मलेरिया और कालाजार इस देश को बहुत बड़ी मौत की तरफ धकेलने वाली बीमारियां हैं। ये फैमिली हैल्थ केअर का मतलब सिर्फ कंडोम्स का प्रचार करना नहीं होना चाहिए। उसका यह अर्थ होना चाहिए कि हमारे देश के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य मिले। वैक्सीन्स मिले, बच्चों को न्यूट्रिशंस मिले, प्रेगनेंट मदर्स को न्यूट्रिशंस मिले। उसकी तरफ ध्यान नहीं है और हैल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में यह बात स्वीकार की है:- Vaccine shortage had affected India's vaccination programme in 2008. Shri Ramdass said that compared to 2007 availability of DPT doses between April and December fell by 3.5 million in Bihar, 6.2 million in Uttar Pradesh and 3.3 million in West Bengal. वह उपलब्ध नहीं है। जिन प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। मैं नहीं जानता कि वे कहां तक सच हैं और कहां तक गलत हैं? अगर वे सच हैं तो बहुत चिंता की बात है। देश में सरकार जो वैक्सीन दे रही थी, उनसे कई गुना दाम देने पर भी बाहर वैक्सीन नहीं मिल रहा है। जो एक बहुत चिंता की बात है। बजट में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह ठीक है कि आप एनआरईजी में पैसा लगा दें, आप किसी तरफ पैसा लगा दें, आप अपने मतदाताओं को धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें वोट दिया है, हम आपको पैसा दे रहे हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि देश की सम्पूर्ण मूलभूत आर्थिक व्यवस्था का जो ढांचा है, जो बुनियाद है, उसको आप कमजोर करें।

अब मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि अभी-अभी आज ही मेरे सामने रिपोर्ट आई है और बहुत चिंता की बात हो रही है कि इस बार सोइंग, बुवाई बहुत कम हो गई है। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, इसे आप देखें। उससे आपका यह 4 प्रतिशत तक जाने का सवाल कहीं से भी हल होता ही नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या करेंगे? आपने अपने बजट में एक्सपोर्ट के लिए कहा है कि आप एक्सपोर्ट में वृद्धि कराएंगे। Support Indian industry to meet the challenge of global competition and sustain the growth momentum in exports. बाहर की

अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? अभी एक रिपोर्ट मेरे सामने है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत चिंताजनक हालात पैदा करती है। यह बैंक ऑफ इंटरनेशनल सैटिलमेंट्स की रिपोर्ट है।

Mr. Joaquin Almunia Mira, Commissioner of Economic and Monetary Affairs of European Union said − Germany's economic output will shrink by six per cent; UK's economic output will shrink by four per cent; French economy will decline by three per cent; Italian economy will decline by 3.5 per cent; Romania's economy will decline by four per cent; Latvia's economy will shrink by 13.1 per cent; Slovakia's economy will decline by 2.6 per cent. Of the 27 nations in EU, only Cyprus will grow. European Union expects its recession to last till 2011 and 8.5 million Europeans will lose jobs over this period. With unemployment hitting 10.9 per cent in EU and 11.5 per cent in rural areas in 2010, EU has revived its GDP estimates for 2010 predicting a 0.1 per cent drop.

अगर वह सिकुड़ रही है तो इसमें हमारे एक्सपोर्ट की गुंजाइश नहीं है। आपको अपना एक्सपोर्ट सस्ता करना पड़ेगा, जब आप एक्सपोर्ट सस्ता करेंगे तो इसके लिए बहुत सोप्स इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे और ड्यूटीज़ के बारे में विचार करना पड़ेगा। लेकिन आपके रिसोर्सिस क्या हैं? यह एक दुष्चक्र है, जिसमें हम फंस गए हैं। यह कहना कि वर्ष 2011 में यह सुधर जाएगा, मैं यह नहीं मानता हूं। आप मुझे पेसिमिस्ट कह सकते हैं, आप मुझे शंकाग्रस्त व्यक्ति कह सकते हैं। वित्त मंत्री जी, मैं पिछले बीस साल से निरंतर कह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट मॉडल पश्चिम ने लिया है, उसके ये परिणाम होने हैं, जो अवश्यंभावी थे और हो रहे हैं। आप उन परिणामों से बच नहीं सकते और ग्लोबल इकनॉमी को जोड़कर अपने यहां की समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते हैं। हम ग्लोब में हैं, दुनिया में हैं इसलिए अलग नहीं रह सकते। लेकिन कितना जोड़ना है, कहां जोड़ना है और कैसे जोड़ना है, इस पर विचार करना होगा। इसके बारे में अब सारी दुनिया ही चिंता कर रही है कि क्या करें। अब बड़े पुराने इकनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के सलाहकार कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन को सुधारने की जरूरत है। It is not working in the interest of poor. It is not working in the interest of all. It does not represent inclusive growth. ये सब बातें स्टिकगालिट्ज कह रहा है, पॉल कुगमैन कह रहा है, वांग हू कह रहा है, जो कोरियन इकनॉमिस्ट बहुत दिनों तक वर्ल्ड बैंक में रहे हैं। इस तरह से यह गड़बड़ हो रही है। हम उससे कितना जुड़ें, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। क्या हम सिर्फ उनकी इकनॉमी को ठीक करने के लिए अपनी इकनॉमी में बहुत से भूचाल लाते रहें? आज दुनिया के 40 देश अनाज पैदा नहीं कर रहे हैं लेकिन वे देश, जो अनाज पैदा कर रहे थे, उनके सामने संकट है। अमेरिका ने अपना सारा मेज़ इथनॉल बनाने में खर्च कर दिया और मेज़ के दाम बढ़ गए, गेहूं के दाम बढ़ गए। आप इस तरफ गौर कीजिए कि किस तरह जुड़ना है, कहां जुड़ना है और क्यों जुड़ना है। वित्त मंत्री जी आप भारत के वित्त मंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मंत्री नहीं हैं इसलिए आपका मुख्य काम भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना होना चाहिए। इसके लिए जितनी बाहरी सहायता की जरूरत होगी, जरूर लेंगे। बाहरी सहायता लेनी जरूरी है और इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दें, यह ठीक नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है। आप पश्चिम बंगाल से आते हैं और आपका साथ बसुदेव जी से रहा है, आप कुछ उनकी भी बात सुन सकते हैं और कुछ हमारी भी सुन सकते हैं। आप मिलकर कुछ कीजिए तभी शायद देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन अगर आप अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या इन शक्तियों की तरफ देखेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा काम नहीं बनेगा। आप हिंदुस्तान की तरफ पहले देखिए और फिर जो बाहर की जरूरत हो उसे देखिए। इसमें हम आपके साथ रहेंगे, इसमें हमारा आपसे कभी विरोध नहीं होगा। हमारा बराबर आग्रह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की बुद्धि, शक्ति और संसाधनों से सुधारने का प्रयास करें। इसमें जहां जरूरत होगी, वहां हम अवश्य मदद देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।

महोदय, आपने बजट में ग्रोथ की बात कही है। मैं देख रहा हूं कि इस बारे में लोगों का क्या कहना है। एक सवाल हिन्दुस्तान टाइम्स ने किया है, आप वह रिपोर्ट देख लें। अखबार कहता है - Has Budget 2009 put forward the right set of measures to achieve the projected nine per cent growth target? 'No', say 86 per cent. Has Budget 2009 fully met India incorporate's expectation from the Government? 'Yes' is the reply of 64 per cent. आपके बारे में यह धारणा है कि इंडिया इंक के बारे में आपने काफी काम किया है लेकिन देश के वे लोग, जो ग्रोथ से जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि ग्रोथ होगी तो देश आगे बढ़ेगा, वे कहते हैं - नहीं। फिर कहा गया - Budget 2009 has struck with a GST roadmap deadline for 2010. Will it be met? 'No' say 75 per cent.

**15.00 hrs**

आपके जो लक्ष्य रखे जा रहे हैं, उनके बारे में अभी तक के जो रिएक्शंस हैं, वे "नो" में ज्यादा हैं, "यस" केवल उन लोगों के पक्ष में है, जो बड़े उद्योग चला रहे हैं। यह भी एक सोचने की बात है। अगर ऐसा है और लोगों में निराशा हो गई कि 9 परसैन्ट ग्रोथ की तरफ बजट नहीं बढ़ रहा है तो मैं समझता हूं कि आपको काफी कठिनाई होगी।

अब सवाल आता है कि आपने इस बजट में साधनों के बारे में क्या कहा। 6.8 परसैन्ट आपका फिस्कल डेफिसिट है। मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानता हूं कि विकास के लिए घाटा कोई गलत चीज नहीं है, उठाया जा सकता है, लेकिन वह प्रोडक्टिव इनवैस्टमैन्ट होना चाहिए। अगर वह नॉन-प्रोडक्टिव है, अगर वह सिर्फ लार्जेस बांटने के लिए है, अगर वह सिर्फ लोन ले-लेकर पैसा लुटाने के लिए है तो माफ कीजिए, वह देश में और अधिक मुद्रा विस्तार करेगा। मैं नहीं जानता कि आपका रोड मैप क्या है। आप कहां से पैसा लायेंगे और उसे किस तरह से इनवैस्ट करेंगे, यह एक बहस का सवाल है। बजट इस मामले में कुछ साफ नहीं करता। ये छः लाख करोड़ रुपये जो आप लायेंगे, ये कहां से लायेंगे? अब सवाल यह है कि आपने यह भी देखा होगा कि टैक्स जी.डी.पी. रेश्यो घट गया और घटता जा रहा है। ...(व्यवधान) अब तो घटता जा रहा है। अब आंकड़े घटने के है, 11 परसैन्ट पर आ गया है और अब जो वर्ष 2009-10 का बजट ऐस्टीमेट है, उसमें 10.9 परसैन्ट है। यह बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ी। आप इस बार इसे बढ़ा नहीं सकते थे, मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन यह भी तो बताइये कि आप ये साधन कहां से लायेंगे, विल यू मोनिटाइज। पिछले साल आपने करीब सवा लाख करोड़ रुपये की मुद्रा बाजार में फेंकी थी। क्या आप यह चार लाख करोड़ रुपये की मुद्रा बाजार में एक्स्ट्रा फिर से फेकेंगे? इसके क्या परिणाम होंगे? अमेरिकन्स आज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो 700-800 बिलियन डॉलर्स बैंकों में झोंक दिये थे और अगर वहां इकोनोमी हीट अप हो गई तो आप देखिये, हमारा और आपका क्या बनेगा। इसलिए इस बात पर जरा गहराई से गौर कीजिए कि पैसा कहां से आयेगा? क्या विदेशों से लायेंगे, क्या फॉरेन इंस्टीटयूशनल इनवैस्टमैन्ट होगा? वह किस जगह करेंगे, वह गांव में तो नहीं करेंगे। वह आपके सोशल प्रायोरिटी सैक्टर्स में तो नहीं करेंगे। उनके इनवैस्टमैन्ट के क्या नतीजे होंगे। लॉंग टर्म के

लिए इस पर सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि इस वक्त आपको कुछ पैसे मिल जाएं और आप कहें कि देखिये यह करिश्मा हो गया या फिर आपने सोचा होगा कि यह आपका आखिरी बजट है, इसके बाद आप इसमें भाग नहीं लेंगे, तब तो अलग बात है, आप कर गये और आने वाला भुगते। इसकी बात मैं नहीं कहता। लेकिन अगर आप इस पर गौर करेंगे तो पता लगेगा कि यह बहुत गहराई से सोचने का समय है। क्या आप डिसइनवैस्ट करेंगे, कितना डिसइनवैस्ट करेंगे, क्यों डिसइनवैस्ट करेंगे, कैसे डिसइनवैस्ट करेंगे, फिर उस फंड का क्या होगा, जो डिसइनवैस्टमैन्ट फंड आपने बनाया है? जो कंपनियां इस समय लाभ से लबालब भरी हुई हैं, क्या आप उन्हें डिसइनवैस्ट करेंगे? वह ठीक है कि आप अपने जेवर बेचकर बनिये का उधार चुकाइये, वह कोई खास बात नहीं है, गिरवी रख दीजिए। वहां मेरा ख्याल है आप कौटिल्य को भूल गये हैं और चार्वाक पर चले गये हैं - "यावज्जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत। भस्मीभूतस्त देहस्य पुनरागमनं कुत ?" वित्त मंत्री जी आप इस तरफ मत जाइये। देश के साधन जुटाइये। मैं देखता हूं कि आपने इंकम टैक्स में जो कमाल किया है, वह बहुत ही एक दर्शनीय चीज है। आपने सरचार्ज घटा दिया और हम लोगों को दस हजार रुपये की लॉलीपॉप दे दी। मैंने इसका आंकड़ा लगाया है, अगर किसी की एक लाख रुपये तक इनकम है तो उसे आज टैक्स नहीं देना पड़ता। दो लाख रुपये पर पहले हमें 5150 रुपये देना पड़ता था, अब यह 4120 रुपये हो गया है। 1030 रुपये की हमें पाकेट मनी मिल गई। इसके बाद तीन लाख, पांच लाख, सात लाख, दस लाख तक यही हालत है। मैं नहीं जानता यहां कितने लोगों की आमदनी दस लाख रुपये है। परंतु जिनकी दस लाख रुपये तक है, उन्हें 1030 रुपये का फायदा है। लेकिन जिनकी 15 लाख रुपये की आमदनी है, उन्हें 37,595 रुपये का फायदा है।

जिनकी 50 लाख रुपये की आमदनी है, उनको एक लाख 45 हजार 745 रुपये की बचत है। यह इनकम टैक्स का खेल है, यह देखने की बात है। पहले तो हम खुश हुये कि हमारी छूट की लिमिट 10 हजार रुपये बढ़ गई है। वित्त मंत्री जी समझते होंगे कि बड़े आदमियों के पास पैसा ज्यादा आयेगा तो वे बाजार में लायेंगे लेकिन जिन कामों में लायेंगे उससे आम आदमी का भला नहीं होगा। इससे देश का उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। इससे देश में बेरोज़गारी मिटने वाली नहीं है। वह रुपया एशो-आराम की चीजों में खर्च होगा। वह विदेशों में घूमने पर खर्च होगा। वह लग्ज़री गुड्स में खर्च होगा। वित्त मंत्री के बजट की दिशा मेरी समझ में नहीं आती है कि यह किधर जाना चाहता है? एक तरफ आप खेती की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं मगर बजट इससे अलग विपरीत दिशा में जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप गहराई से इस ओर ध्यान दें। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुये यह देखें कि इस साल जिस विभीषिका से देश गुजर रहा है, उससे ज्यादा विभीषिका में न फंसें।

उपाध्यक्ष जी, मुझे चिन्ता है कि जिस तरह का इस बार मौनसून है, क्लाइमेट चेंज है, इस साल अगर फसल 10-15-20 परसेंट भी कम हो गई तो आपको भारी कीमतों पर अनाज बाहर से आयात करना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री जी, चाणक्य ने कहा था कि आने वाली विपत्ति को ध्यान में रखकर राजा को प्रबल सैन्य का प्रबंध कर लेना चाहिये। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप ऐसा प्रबंध करेंगे तो देश को विपत्ति से बचाने वाला होगा, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आपके बजट से देश पर विपत्ति आने की गुंजाइश होगी, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हम आपका समर्थन नहीं करेंगे।

DR. K.S. RAO (ELURU): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for giving this opportunity to speak on the General Budget, particularly after the speech delivered by the senior Member, Dr. Murli Manohar Joshi, who is a very popular, educated and a learned man. However, I wish to give my opinions on this based on my beliefs.

I am happy that hon. Member Murli Manohar Joshiji has admired your Budget to begin with. He said that you have set a very good target and that he would be very happy if they are achieved. He was only skeptical as to whether you will be able to mobilize the resources that are required. He was saying that he was of the opinion that the economy was not on the right track. He dealt with several issues like agriculture, eradication of poverty, employment, water management and what not. I am happy today that the senior BJP Member has dealt with agriculture. To the best of my knowledge, in the several Budget Sessions that I had attended, only lip-service was shown for agriculture, poverty eradication, but no concrete suggestions have ever been made either as Opposition Members or as ruling party Members, when they were in power.

I would not have referred to the Budget of 2004-05 of the UPA Government, the first Budget of the UPA Government, but for the fact that hon. Joshi has referred to it. In 2004-05, as he said, seven clear objectives were spelt out by the then Finance Minister Shri P. Chidambaram to maintain a growth rate of 7-8 per cent. In spite of the fact that there was recession during last year, the UPA Government has achieved an average growth rate of 8.5 per cent in the last five years.

Another point is about the universal access to the basic quality education and health. They had levied two per cent cess on the tax-payers and, to begin with, collected Rs.5,000 crore. Now it has gone to Rs.13,100 crore exclusively for primary education. The allocation for education is essential for any poor man to survive or come up in life because the education is the only best instrument for any poor man or middle income man to come up in life. The allocation to education was given only by the UPA Government. A poor man felt like even stopping his boy of ten years from going to school. He felt that he may not fetch anything; he may not get employment and thereby sent him to earn a wage. In spite of that, the poor man has not come up so far in his life or is not in a position to have a house of his own. That was realised by the UPA Government. It is not merely an eye wash or a lecture or just touching it tangential to issues. It is a question of going deep into the matter. It saw that the dropouts have come to a very bad level. If hundred boys are to be admitted in a primary school, by the time they reach the university, there are only nine per cent left. So, to attract the poorer sections particularly in villages, the hon. Finance Minister has allocated Rs.36,400 crore to education alone and out of which Rs.13,100 crore are for Sarva Shiksha Abhiyan and Rs.8000 crore for mid-day meals programme. Not only that. The experience of every one of us is that funds are available in plenty in regard to constructing a building for a primary school or a facility for educational institutions. We are doing it in a very liberal way. All this is because of the big allocations made for the education by the Government of

India apart from the allocations made by the State Governments.

One of the seven things which he mentioned was about generating gainful employment. It is not only for just making a statement or giving a promise in the Budget. The NREGA was immediately implemented. We have assured to those unfortunate people who will have only seasonal work in villages, that they would have now work for at least 100 days in the off season. The Government has assured by this Act, a right for 100 days work for one member in each family. Hon. Joshiji may say that the work for only 43 days has been given and not 100 days. It may be true. I do not deny it. But the intention of the Government is to provide it wherever it is required. I am an eye witness to that. In an area where wetland is there, even if the Government is prepared to give work for 100 days, they are not coming forward because they are earning a wage of Rs.150 to Rs.200. We have even increased wage remuneration to Rs.100. They may not come, they may go to some other place. If the numbers were to be less than 100 days, it is not the fault of the Government. He must appreciate that. It is not only the numbers but the Government has gone to the extent of telling that if in a village, if a worker asks for a work and if the Department or the President of the Village Panchayat do not find the work there, it is the responsibility of the Government to pay him even by keeping him idle. Does anyone think that this Act was a wrong Act? Is it not providing employment in our rural areas in large numbers? Contrary to that, it is not my intention to criticise but to express my opinion.

When hon. Shri Joshiji was speaking about employment, he was telling that the way for increasing the employment in this country was to increase the exports and exports are to be cheaper. Does everyone think that, that was the only way to provide employment or to increase employment opportunities in this country?

How many millions of people can be employed in the exports sector? Even if all of us are to be ready to sell our products at much cheaper rate compared to the international rate, how many can be employed? On the contrary, hon. Minister has said that he wanted to bring 50 per cent of women folk into the fold of the Self-Help Groups; ready to provide both capital subsidy as well as interest subsidy and a loan of Rs.1 lakh. My own experience is, in my own constituency, in West Godavari district, which stands high in terms of Self-Help Groups, 58,000 Self-Help Groups are formed. All must see the glow in the faces of the women; the courage, the confidence, the smile and the pride by just taking Rs.1.50 lakh for the entire group − maybe Rs.15,000 by each member. By taking this Rs.15,000, they could earn Rs.2,000 to Rs.3,000 per month. Apart from the income that is raised by her husband or father, maybe Rs.2,000 is a too small an amount for you and me. But if they were to be in need of Rs.100, for generations, they have been depending upon their parents, husbands and sons. Today, they have money with them.

By encouraging the Self-Help Groups all over the country, by putting a target of bringing 50 per cent of the women into this fold, the employment that you are creating is more than 50 million. The age group between 18 and 65 is 600 million in this country. Presuming 300 million are men, and 300 million are women, half of that is 150 million women can become members of SHGs. It may not be possible for us to bring all of them into the fold of Self-Help Groups today, in one year.

But the only problem is this. Hon. Finance Minister, Sir, there is a glow, there is a confidence, there is ability, and there is a will on the part of women to use this money. All that we have to do is, let us reduce the rate of interest on loan that is being given to them. Let it be three per cent. Let us also find a way to market their products. If we can do this, nobody can question us for generations to come as to whether we are providing employment or as to whether we are improving the economy. They would generate the wealth for you. It is not nine per cent. I know that. You fixed up the target in spite of the international and global meltdown. That shows your confidence on the economy in this country. That is where you understood the robustness of the Indian economy. To provide employment, that is the best way. Already we have provided employment through the NREGA. I am happy about it.

I was also telling and he also gave a good suggestion in this regard. Apart from the areas which you have provided for forming an asset, while providing employment to the villagers, we have to extend the scheme. Till the other day, roads were not included. Now, we have included roads. That means, we are providing employment, we are utilising the assets, and we are creating the asset in the village. In this context, I would like to make one more small request that not all the works contain only human labour. There is also a percentage of material component. So, if you were to include that, do not need to put 50 per cent or 60 per cent, if it were to be, may be 30 per cent to 40 per cent material component, to be included, and accepted under the NREGA, we can really form assets in the village, which can be used for generations.

For example, water bodies. He mentioned about water bodies. Yes, we employ human labour in desilting. But if a structure is to be made to retain the water, you require a material component also. I have a humble request in this regard. Hon. Member was also telling that this must be extended to village industry and the cottage industry. I agree with him. If that were to be so, Rs.39,100 crore which has been allocated, would be an excellent asset to the nation.

The allocation of Rs.39,100 crore will create more than Rs.1 lakh crore of assets in this country. Here, I am talking only about the rural areas and about NREGA.

The hon. Member was telling that the tax-GDP ratio has come down. I do not know, where he has seen that. He might have seen in some papers. I have seen this in the book − the tax-GDP ratio has gone up. It was earlier 9.2 per cent and last year, it was 11.5 per

cent. That is one of the best indications for this country where the tax ratio is going up. He was also sceptical about how we are going to get the resources which are shown in the Budget. But the Budget shows no increase in resources; it is only Rs.2000 crore. By the taxation measures, he has added only Rs.2000 crore. By increasing the slab, who are benefited? They are senior citizens, women and ordinary persons. Maybe, he has removed surcharge, but still he has withdrawn many exemptions, which were taking away the tax revenue.

We discussed many a times in the Standing Committee on Finance. We suggested that these exemptions are to be withdrawn because some people are taking advantage of all these exemptions, particularly the corporations and multi-nationals, and they are reducing their tax burden. So, we suggested that we should remove it. He has done it. We must appreciate that. He has also widened the tax base; he has widened the tax-payers' number. It was around Rs. 3 crore. He wanted to increase it. He said that if a person's turnover is Rs.40 lakh, he could voluntarily file a return, he will not be embarrassed and he will not be harassed by any officer from his side; he only has to declare eight per cent income; he need not have to maintain a book of accounts also.

So, what he has done is simplifying the procedure and making it simpler, not making it complicated. So, in that way, what he has done in this Budget is excellent.

My intention is not to criticize. I will tell what the hon. Minister has done in his Budget. Basically I always believe that the duty of the Parliament or the duty of the Government of India is to enact legislations which motivate a man to work, to sweat, and not to demotivate. It should motivate a person to work. It must create a congenial atmosphere; it must regulate. But the Government does not need to do everything. We are doing that now.

I have seen that it is there even in his proposal of disinvestment to a limited extent of only five companies, unlike what the NDA Government had done earlier. In the NDA regime, it was a policy of disinvestment everywhere. But the present Finance Minister did not do that.

It was late Pandit Nehru who believed in socialistic democracy and wanted to encourage the public sector undertakings particularly in core sectors, in those days when there were no investors in India, when our entrepreneurial talents have not gone to the large extent in comparison to others. So, the core industries were kept in the public sector and that was nourished. That is why today we are not short of core items. We are producing our own requirements − be it steel, be it cement. We are in surplus; we are in a position to export. That was the policy at that time.

Once again, I would say that I have never seen a BJP Government speaking in terms of deep commitment to farmers or poverty eradication. These are not my words. I will tell you what is in their Budget. What is there in the Budget of the year 2003-04? I will not go too far back; I will only speak about the 2003-04 Budget.

I just want to remind the former Finance Minister what exactly he thought about, what was the thought process or what was his conviction then. Sir, 2003-04 Budget speech was made by the then Finance Minister, Shri Jaswant Singh. He talked about five priorities of the NDA Government:

1. Poverty eradication, which I would say is an excellent idea.
2. Health, which nobody can deny.
3. Housing, this is the basic requirement of a poor man.
4. Education, without which no common man can come up.
5. Employment, which is another important area.

But, what was his conviction in regard to these? I would like to quote. "My opinion always is, it is not coining the language and words, it is the intention, your thought process or the commitment to what you say." What did he mean by saying that? He wanted to improve the education. What did he do in the Budget for improving education? He gave IT exemption of Rs.12,000 per child and Rs.24, 000 for two children. The then Government thought it can improve education by giving IT exemption. Who pays the income tax or who requires IT exemption?

Book authors are exempted from income tax for the royalty up to Rs.8 lakh. That is how they thought education can be improved!

I now speak of the health. What exactly they thought can promote health? To promote India as a global health destination, they wanted to increase the healthcare situation in the country. Incentives were given to private hospitals having more than 100 beds. Who construct such hospitals? Can a poor man at any time have excess to a corporate hospital? They gave 40 per cent depreciation on life saving equipment. By announcing reduction of customs duty on life saving equipment and drugs they wanted the healthcare to reach the common man!

I dare tell in my constituency, for generations even if wife, husband and child were to work from 6.00 in the morning to 6.00 in the evening, it is unfortunate that till today there are millions of people who cannot purchase even a house site or who cannot imagine to construct a permanent house of their own. Every one of us says that housing is very important, more particularly for the economically weaker sections. What was the view of the NDA Government with regard to housing? The view was, giving incentives for slum upgradation by giving a land to the real estate development. The second exemption they thought was to give exemption in interest up to Rs.1,50,000 for salaried people for houses. What kind of houses they can build to get the exemption of Rs.1,50,000. UPA Government was giving Rs.40,000 to every house. There are poor people who are not in a position to construct houses by investing Rs.1000 of their own. Will this exemption of Rs.1,50,000 help the poor man in any manner?

What kind of thinking they had on employment. Hon. Murli Manohar Joshi ji has said just now that exports is the best way to improve employment or reducing the prices of Indian products in the international market is the best way to improve employment. What did Shri Jaswant Singh think about it? He thought that employment can be improved by increasing the standard deduction to 40 per cent of the salary or providing Leave Travel Concession to both salaried and retired employees so that they can live with dignity. These are his words and not mine. This is how he believed that the poor man's life can be improved in this country and the employment situation can be improved in this country.

The employment can be improved in this country and the housing for poorer sections can be achieved. What has the UPA Government done? I will tell you what the UPA Government has done. As regards education, I have already told you that they levied two per cent cess on the tax in the first year and collected Rs.5000 crore and spent it on primary education. Today, the hon. Minister has allocated Rs.39,000 crore and for Mid-Day Meal - Rs.8000 crore and exclusively for primary education from Government of India Rs.13,100 crore were given. Money has also been allocated for higher education, distance education and technical education.

I would like to mention one thing which is not the subject of the hon. Finance Minister but he is very much connected with this. The present system of education in India is irrelevant to Indian needs. Maybe, the system of education was made during Britishers time to prepare clerks without giving any sharpness to our brains or without preparing the Indians to do something productive work. Today, we have started AICTE. We have started technical education. Today, we are introducing vocational education even from eighth class. Today, we have allocated Rs.1500 crore for skill development. How will wealth be generated in our nation? We all know that we have got the largest technological manpower in the entire country. But it is a pity that in the IT sector where India is admired by one and all, software technologists are indented from countries like Germany, Japan, UK, and Europe. Today we find that the relevancy of the Indian software technology to the Indian industry is not in tune. You tell me in which profession can we get a skilled man. If you want a driver, there is no good driver. If you want a technician to repair your scooter or car, there is nobody. If you have a problem in your household things like repairing small light or radio or TV, there is nobody. You have to search and waste your time only to catch hold of one person. So, my humble request is that let the Government concentrate entirely on skill development. It is not higher education like MA or BA or Ph.D. which alone matters. I am an engineer but what did I learn during my engineering course. I only know A,B,C,D, etc. I came to know that when 'c', 'a', 't' are put together, it will become a cat which mans *billi* and that I came to know when I entered into my life and not in the college. So, we have to create skilled persons. We should have skilled persons and the Government should be serious about it. I calculated that if they were to allocate a few thousand crores of rupees every year, even people who are uneducated in the villages can be trained in some profession or the other. They can generate wealth for this country. If the hon. Member, Mr. Joshi were to be sceptical about the ambitious 9 per cent growth which you are confident of achieving, by improving skills in this country you can go to 13 per cent or 14 per cent. You can compete with China. Today, hon. Members on the other side are comparing our country's progress with China which they never did earlier. Today, they compare China with India. I agree that China has progressed and I am only happy to the extent that they are prepared to cooperate in this regard. If that thinking were to be there, that is enough. When it comes to the development of the nation, we are all one. We fight in the elections. Let us propagate what we believe and let us try to win through our Parties. But when it comes to taking a right decision, you can always criticise if it is a wrong decision. Nothing wrong in it.

Sir, my next point is on agriculture. What does a farmer require? A farmer requires adequate credit and crop insurance. For no fault of a farmer if he loses his crop in a cyclone, then who has to come to his rescue? If a trader or an industrialist were to lose Rs. 100 crore worth of property by way of a fire accident, then there are insurance companies who are prepared to pay for that loss. But what about a farmer? A farmer wants crop insurance and remunerative price for his produce. I am happy to say in this regard that for long five years the price of paddy was stagnant at Rs. 580 per quintal, but during the UPA regime the price was enhanced to Rs. 930 per quintal.

Sir, at one point of time an all Party meeting was held in my constituency where representatives from all Parties were present and I, in spite of being a Congressman, said in that meeting that Opposition parties will sit on roadside and criticise the Government saying that the Government is not giving remunerative prices to the farmers who are the backbone of this country and so the Government in power is incapable and hence needs to be brought down. But if the same Opposition party were to come to power they would forget about the interest of the farmers. What is the reason for this? The reason being that if the Government were to increase the

remunerative price of the farm produce, then the prices of essential commodities will go up like anything and in that case again the same Opposition party will start *dharnas* about the prices of flour, ginger, black grain and all. They would say that yesterday the price of this commodity was Rs. 10/- and today it has shot up to Rs. 20/-; yesterday the price of edible oil was Rs. 30/- and today it has shot up to Rs. 60/-. So, this is an incapable Government and this Government should be brought down. Then I said that no matter whether we sit in power or not, even if we were to lose for one term it should not be a problem because unless the Government is bold enough to increase the remunerative prices for farm produce, no Government of any party will be doing justice to the farmers in this country. I am happy to an extent; I am proud to an extent that this UPA Government did increase the remunerative price of paddy from Rs. 580/- to Rs. 930/- and that was the reason why we found an increase in the inflation rate during the last one year. When there is increase in prices of foodgrains, naturally one can imagine what kind of inflation could be there and consequently what kind of an uproar all around would be there. But this Government did it. I would like to appeal to the hon. Finance Minister that this Government has five more years to go and so my explanation is that if the remunerative prices of farm produces were to be increased and the farmers were to get remunerative prices, then what will happen is that the wealth will get shifted from the urban areas to the rural areas. Who would be affected by this? 65 per cent of our people live in the villages. We have the Public Distribution System in place. Now we are giving rice at Rs. 3/- per kg. So, whatever increase in prices would be there would not affect the poor man in the villages. Questions may be asked about the quantity being given. One may argue that their consumption need is 50 kg. but only 25 kg. is being provided. But the moment the prices are increased, the wages also will go up in the villages. So, a wage earner in a village will not be affected. Then, who is going to be affected? It is the middle class in the urban areas who will be affected. A rich man will not be affected. What percentage of his income does a rich man spent on foodgrains? He does not care. So, if the Government were to increase the remunerative prices of farm produces, then the objective that would be achieved is that it would shift the money from the urban areas to the rural areas. There will be real growth in the villages.

Sir, I was shocked to learn and everyone of us are aware that one day's increase in share price has increased the capital value of industrialists by Rs. 5,60,000/-.

Is it by sweating or hard work that they have got it? How can a share of an industry go from Rs. 10 to Rs. 2000? It is obvious that he is selling his product at an exorbitant price. And you tell us that which farmer could purchase one acre of land out of his income from 20 acres crop. Which farmer today is in a position to educate his child out of his produce? No farmer will be able to do it. If somebody were to purchase some land in a village, it must be his son or daughter who is employed elsewhere or has business elsewhere or a businessman from outside must come and purchase it and not a villager. You have done excellently well in this direction. We have increased the credit. Shri Rajiv Gandhi has brought the crop insurance scheme and we have seen it a lot of years. Now, it has to be shaped or corrected in a way that really goes to the rescue of the farmer. Earlier it was on mandal basis and today, we have made it on a village basis. But something more has to be done to see that they are helped.

As regards employment, you have already promised to encourage the Self Help Groups run by women. I have met Chairmen of several banks during our meetings. Everyone of them said that they will lend any amount to the Self-Help Groups because recovery is 97 per cent. What more do you require? Even in industries, recovery was not 97 per cent.

Regarding rural development, today, you have made a provision of Rs. 80,770 crore and particularly, in regard to the PMGSY, you have provided Rs. 12,000 crores. When you go to a village, every villager will ask for concrete roads or a road connecting his village and another village. Today, all of us have realised the importance of the infrastructure. Infrastructure does not mean only connecting Delhi and Mumbai. It also means connecting villages. So, you have a provision for it and we are happy about it but let it be ensured that State Governments also come forward to add their money in this regard. For highways, you have given Rs. 20,.450 crore. I am very happy about it.

I am of the opinion that as far as economic Ministries are concerned, budgetary support need to be reduced year after year. We do not need to give it to the power sector, civil aviation and the railways. They must earn on their own. If the railways were to have assets worth lakhs of crores, should they not earn money from them? Should they look to the budgetary support every year? If you are to give a loan of Rs. 4 lakhs to a driver for purchase of a truck, you are charging interest, he has to repay that Rs. 4 lakhs and then you ask him to pay service tax, income tax but still he has to repay that amount. Why not the railways or the civil aviation? If the railways is short of money, let them raise bonds or as you have suggested let them go in for PPP. It is an excellent way for them. Whatever be others' thinking, in a changed atmosphere, we need to have a private investment. You cannot avoid it. While accepting a private investment, you have stringent terms where it becomes an asset of the country over a period. If a road is to be built under BOT or annuity, within ten years or four years or six years, it becomes a Government property and a road with quality or a railway line with quality. So, let us formulate a procedure or the terms by which we can encourage private investment and involve them in anything. They are ready for it. The only thing is that if we were to be liberal, somebody might exploit them. Others will look at it and they also want to do the same thing.

In regard to health care, I have been writing letters also. The hon. Minister has introduced Swasthiya Bhima Yojana. In the NDA Government also health insurance was there. But how many people were insured over the years? It was only 11,000. But the hon. Minister has said that he would extend this health insurance cover to all the BPL families in the entire country. I am very happy about it. It does not really cost the exchequer more if you see the benefits later on. What happens is that there will be confidence on the part of doctors also to go to the rural areas. It is because when the rural people are insured, the doctors are also assured of payment. The wife and husband will go and practice in a village, which they are not prepared to do now. If the hon. Minister were to extend it to all the BPL families, it can be for a specific amount. It need not be a lakh of rupees or two lakh of rupees. As the hon. Minister said, it can be for Res. 30,000 or for Rs. 40,000 in a year.

In Andhra Pradesh, the Chief Minister has started *Arogyasri* scheme to cover the major diseases, like heart attacks, cancer, kidney, etc. We are very much popular. When we go to the villages, everybody speaks about that. It can be extended to other diseases through the insurance. Now, what is the position of a poor man? If he were to get a sudden heart attack or meets with an accident and if he goes to a Government hospital, nobody will care for him. They will say, "No bed." He will have to wait for hours together outside. Can he go to a corporate hospital? He cannot think of making the payment. Then, what is the course left for him? He has to leave it to God as to how many hours or days or years he would live. If the hon. Minister extends it to the entire BPL families, the whole nation will be with the hon. Minister.

We have to generate wealth. But if we just generate wealth and if it does not reach the common man, then it is of no use. There will be only billionaires. So, the "inclusive growth" which the hon. Minister mentioned is the best course to adopt and it has to be totally implemented. For that, we do not need to give crores of rupees to an individual. No poor man in this country is asking for lakhs of rupees or a big building. He is only asking for basic needs, like a ration card, food at reasonable price, shelter, health card, school for education, etc. These are the minimum needs that he is asking. Later, if you develop the communication system, infrastructure, etc. in the villages, no villager will prefer to go to a city. Today, a daughter of a farmer who owns 20 acres of land, prefers to marry an Attendant in a bank rather than an owner of 10 acres of land in a village. How pathetic is the condition of the farmer! They are prepared to pull a rickshaw in a city rather than living in a village. Let us change this trend by such type of allocations and convictions.

Unless the villages become rich, unless the income of the villagers goes up, who will purchase those commodities or products which are manufactured by the industrialists? If an industrialist manufactures millions of cycles, who will purchase them if the people do not have the purchasing power? Will he export it all the time to some other country? Basically, we have to see the needs of our own people. So, unless the purchaser is there, where will the manufacturer sell his goods?

Why is America interested in us? Why is America loves us and China? It is because of market for their products. They think that with even thirty to forty per cent of the middle class population − which comes to about 400 million − they will have enough market, while we do not look at the needs of our own people.

The hon. Minister is transferring Rs. 71,000 crore to the rural areas by way of waiving the debt. It is not only helping the farmers, but it is helping the rural economy as well.

Now, I am happy that the hon. Minister has extended this date up to December. Only four days back when I went to my constituency, all the farmers came to me. They said, `Sir, we do not have any money to pay back immediately as you know our situation. So, at least, extend it for one month.' They were asking only for one or two months. Now, the hon. Minister has extended it up to December. The entire farming community is grateful to you.

The hon. Minister has also said about the GDP growth and economic recovery. He believes in the coordinated efforts between the States and the Centre. This has to be impressed upon. He must impress upon the State Governments also. They cannot be irresponsible. Their actions are going to impact the Indian economy as a whole. As he was telling, now with globalisation coming in, it is not only the country, if one State were not to fair well or use money liberally, then it will have an impact on other areas also. As he has said earlier that he is calling a meeting of the Chief Ministers of various States, this point also must be brought to their mind and impressed upon.

The hon. Minister has increased the facility to the State Governments also by .5 per cent of the State GDP wherein they can raise loans to the extent of Rs. 21,000 crore. But let them be responsible to pay back that money. Let them not think that they can waste their money on some unproductive ways. Many of them are raising the debts and using them for unproductive purposes where they can not repay these loans. When a State Government or a Central Government raises a loan, they must think for what purpose they are using it. If it were to be for a welfare measure, it is part of your responsibility; if it were to be for any other thing, then there must be an asset created. Out of that asset, they must be able to pay back the loan. That must be the thinking on the part of not only the Government of India but also on the State Government as well.

Sir, the hon. Minister was questioning about the fiscal deficit of 6.37 per cent. He has said while reading the Budget Speech that he did it not on his own − he does not have pleasure in doing so -- and he has done it only to stimulate this economy. At a time when the

global recession was there and our banking industry and finance industry was not affected as much, he wanted to give life to it. He did it by which what we promised to the nation, reducing the fiscal deficit to three per cent. We did bring it to 2.7 per cent earlier or making it zero over a period. We brought it to 2.7 per cent in 2007-08 with a view to stimulate the economy. Definitely, we will bring it back once again over a period of time. So, unless we do this today, there will be further recession. So, that can never be misunderstood by any person in this regard of his spending about or making available Rs. 1,86,000 crore to the industry and to stimulate the economy.

The hon. Minister has said about infrastructure. He has created infrastructure finance company to refinance the bankers to an extent of 60 per cent of the loan for which he has provided a lakh crore of rupees. This will definitely help infrastructure in a big way which is languishing to an extent today.

The day the hon. Minister made his speech, there was a total confidence on the part of the people who were involved in the infrastructure. They will come with double vigour. They will make more investment which they were not sure whether they will get back their investment earlier, if they were to do so. Now, not only your one lakh crore of rupees, even private investments can come in a big way because of your assurance.

As far as export growth is concerned, my friends from the Opposition are more interested. I do not want to make a big explanation or a big description of it. But I am definitely of the opinion that the trade balance has to be maintained. We cannot always be minus exporters. So, we must also think in terms of maintaining the trade balance in that regard. I am not of the opinion that creates a terrible employment and all that. But keeping in view of the foreign exchange, we must improve our production and export.

It is enough if we do not import food grains. If we are to import two million tonnes of food grains, the day the world nations come to know that India - which is the biggest consumer of food grains in the world - is in need of food grains, the prices will double in the international market. Then, what about the money that we will lose? If we can prove that we do not need a kilogram of imported food grains for our nation, the price will fall like anything. So, I am sure of that.

In this regard, you have given enough incentives to the exporters also to once again motivate them and then instil confidence in them. I have been requesting the Government − You have also said about it − to initiate medium term measures, to have stable balance of payments and moderate interest rates. I have made a study of it a couple of times. You are very much learned than me. The important point is that the interest rates are killing the people of the entire nation. I am of the opinion that if I have a million rupee with me, I will not work because my money earns money. I have no value. So, the human value or human rating or the capacity to earn or the importance of the human effort is coming down. If the money were not to earn so much, if the rate of interest is two per cent or three per cent like in the West, then, everybody will work; everybody has to work. People cannot depend on the treasure they have. So, money should not earn money; human being must earn money by sweat, hard work and using intelligence. Then only everybody will try to learn some skills; then only everybody will depend on himself rather than depending on his ancestral property or the treasure that is lying with him. So, I would request the hon. Minister to once again discuss with all the financial experts in the country including the Reserve Bank Governor and the bankers to reduce the rates of interest. I agree that some logic that is put forth is that we have the highest rate of savings in the world which is more than 38 per cent. But savings need not be the core thing for investment. Because of the reduced rates, people will not go elsewhere. Instead of putting in the bank, they will put it in the shares, invest in the shares and money will not go outside. Their savings will remain. Investment will change the route. So, I would request you to think seriously of reducing the rates of interest.

I am very happy that you have said a word in the Budget about the direct transfer of subsidy on fertilizers to the farmers. An impression is there in the country that the sick units like the Sindri Unit are having the oldest technology in producing fertilizers. I have seen the statistics. In the case of the Madras Fertilizers Factory, the rate for manufacturing a tonne of urea or something like that is Rs.500 whereas in some other factory, it is Rs.5,000/- There is so much of a variation. They are giving subsidies. So, nobody will make an effort. You said that you would bring in competition. Let them go to hell. Let them find the latest technology in the world. Let them work hard. Let them reduce the salary or do whatever they want but let them produce, in a competitive way, all the fertilizers. If we continue to give subsidy to the producer, there will not be any incentive for him to reduce the cost of production....(*Interruptions*)So, your promise of transferring subsidy to the farmers is excellent.

Sir, you have said about food security. It is wonderful. If we were to really provide the basic requirement of rice or wheat at Rs.3 a kilogram, if we were to provide 25 kilograms for every family living below the poverty line, then, we have to do one thing. My hon. Colleague earlier told that the number of people living below the poverty line, as revealed by the statistics collected by the Government, is 28 per cent. But if we go to the villages, we can find more number of people. So, in regard to the provision of 25 kilogram of rice or wheat to be provided to the people living below the poverty line, I would request you to make some re-assessment of the BPL families in the whole country and then provide this accordingly.

Similarly, I want the Government to think, in association with the State Governments − though it is not your subject − of providing the basic requirements like edible oil, *dhal*, sugar, tamarind, kerosene, cooking gas, etc. at the specific subsidised prices to the poor

people so that they can think of how to come up in life on par with the rich people.

**16.00 hrs.**

Otherwise they will change their life style in one decade or two decades instead of waiting for hundreds of years to change their life style.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. There are more than 20 Members from your party who want to speak on the Budget. Please think about them also.

DR. K.S. RAO : Sir, the Finance Minister has introduced a pension scheme to the unorganized sector. He is providing pension to the people in the unorganized sector and also through Indira Gandhi National Pension Scheme. I wish that this pension must be paid to all those eligible people who are more than 60 or 65 years age and who are living like orphans in villages where their own children are not in a position to take care of them. So, I wish that they should also be taken care of.

Then, the hon. Finance Minister has brought the New Pension Scheme. Though the Members of the Communist Parties will come in the way, the Minister has to implement it immediately so that the gap will be covered and really they will be benefited over a period of time. It may not be known now because the actuarial calculation is not known to everybody.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

DR. K.S. RAO : Sir, I do not want to take more time of the House. But I am of the definite opinion that this Budget, which the hon. Finance Minister has presented, has been praised by one and all. The only thing that we wish is that if the basic requirements of the poorer sections of the society in the country as a whole are to be taken care of in 5 years, it is a revolution. China will stand nowhere. Indians are the most intelligent people. They have proved themselves when they left the country and gone abroad. As long as they were in this country, their talents were not recognized. But the moment they went outside, they have become Nobel Prize winners. So, let us have faith on the capacity of the poor man in this country also. He can also generate wealth, given an opportunity, given the motivation and given the support from the Government.

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे सामान्य बजट पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जहां तक बजट पर बोलने का सवाल है तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से बातें आई हैं और यह नहीं कि हम अपने दल की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो हम बजट का विरोध ही करेंगे, बल्कि कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे। यह बजट आम आदमी का बजट तो लगता नहीं है। पहले बजट के प्रति लोगों में उत्सुकता रहती थी कि आज बजट पेश हो रहा है तो कौन-कौन सी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, किस-किस वस्तु के दाम घटेंगे, यह एक जिज्ञासा रहती थी। लेकिन अचानक रात्रि में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो लोगों की उत्सुकता खत्म हो गयी और बजट के प्रति जो लगाव था वह खत्म हो गया। देखा जाए तो यह बजट आम आदमी का बजट न होकर खास आदमियों का बजट लगता है। कुछ कारपोरेट घराने ऐसे हैं जिनको लाभ देने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें लाभ न दिया जाए। मेरा कहना है कि देश के अंदर बहुत से ऐसे कारपोरेट घराने हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में अपना योगदान देते हैं। जैसे सूचना प्रौद्योगिक विशेषज्ञों के लिए आपने 100 करोड़ रुपया दिया और कहा कि नागरिक सुरक्षा हम मजबूत करेंगे और सभी नागरिकों का पहचान पत्र बनाएंगे।

**16.04 hrs.**

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the chair*)

आपने मतदाता पहचान-पत्र भी देश में बनाया था, लेकिन कितना सफल वह हो पाया है यह बात 20 साल से आप देख रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बात बड़े जोरदार तरीके से कही गयी थी कि 100 दिन के अंदर हम देश के अंदर क्रांतिकारी व्यवस्था ले देंगे, हम देश को तरक्की पर ले जाएंगे और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार के सामने पांच चुनौतियों भरे विषय हैं जिनपर सरकार को ध्यान देना

है।

सभापति महोदय, जहां तक खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात कही गई है, उसके बारे में मैं मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में 20 करोड़ लोगों को ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा है और 50 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं। सरकार ने कुपोषण समाप्त करने के लिए व्यवस्था की है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर देखें, तो उसका सही स्वरूप हमें दिखाई पड़ेगा। देश में सालाना पांच लाख महिलाओं की मौत प्रसव के समय हो जाती है। अगर हम ग्रामीण स्तर पर देखें तो आज भी 80 प्रतिशत भारतीय स्वास्थ्य उपयोग का उपयुक्त ढांचा है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

दूसरा आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। बजट में व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा में पूरे विश्व में आज विभिषिका है, उसमें भारत का छठवां स्थान है। 1970 से लेकर 2004 के बीच आतंकी घटनाओं की संख्या 4100 है। देश के 14 प्रदेशों और 602 जिलों में नक्सलवाद है, जिससे वहां का विकास भी रुका हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो 15 से 19 वर्ष के बच्चे 71 प्रतिशत सैकेंडरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको सही स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद ही दिखाई देगा। रोजगार सुरक्षा की जहां तक बात है, संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन ने विश्व स्तर पर छाई मंदी 2009 की बात कही है, उसमें दुनिया में कम से कम 21 करोड़ नौकरियों का नुकसान होने वाला है, उसमें भारत अछूता नहीं रहेगा। आज भी आईटी, बीपीओ सैक्टर में छाई मंदी से निपटने और नए रोजगार सृजन करने की चुनौती सरकार के सामने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने नरेगा में पैसा दे दिया तो रोजगार सबको मिल जाएगा।

जहां तक ऊर्जा और पर्यावरण की बात है, उसकी तरफ हम ध्यान दें, तो देश के अंदर केवल चालीस वर्ष के लिए पर्याप्त भंडार कोयले का हमारे पास है। उसी से हमें थरमल पावर प्लांट चलाने हैं, उद्योग-धंधे, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रख कर आर्थिक मंदी से पार पानी है। तेल के भंडार के बारे में सोचा जाए, तो जो सर्वेक्षण आपके पास है, केवल 20 वर्ष के लिए आपके पास भंडार बचा हुआ है। यह बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। बहुत से सांसदों ने सदन में बात उठाई है, जब राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात होती है, आज 57 प्रतिशत भारतीय बिजली उपयोग से वंचित हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े गांवों में काम हो गया है, छोटे गांवों में काम नहीं हुआ है। यह सोचने का विषय है। वित्त मंत्री जी चले गए हैं, उन्होंने अपने बजट भाषण में महान अर्थशास्त्री कौटिल्य जी की बात का जिक्र किया है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महान अर्थशास्त्री कौटिल्य ने कहा कि जनता पर आय का दस प्रतिशत से कम टैक्स नहीं थोपना चाहिए, अन्यथा वैमनस्यता और अपराध बढ़ेगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आज जो वैमनस्यता और अपराध बढ़े हैं, उसका क्या कारण है? जितना हम टैक्स लगाएंगे, महंगाई उतनी बढ़ेगी। महंगाई के विषय में मेरे ख्याल से इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जहां तक किसानों की बात है, हम समाजवादी पार्टी की तरफ से आते हैं। किसानों के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपने एक मुश्त ऋण माफी की बात कह कर कि 75 प्रतिशत जमा कर दीजिए, तो 25 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी। पिछली बार आपने सीमांत लघु कृषकों के ऋण माफ करने की बात कही, इससे आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। कृषक का उत्पादन में जो खर्च लगता है, उस हिसाब से उसे उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाता है।

जो आत्महत्याएं हो रही हैं, वे रुक जाएंगी। यह अभी रुकने वाला नहीं है। अभी मैं रायबरेली के बारे में लाया नहीं हूं वर्ना मैं रायबरेली का जिक्र कर देता कि यूपीए की चेयरपर्सन के निर्वाचन क्षेत्र जिले में एक किसान ने आत्महत्या की है। उसने ट्रैक्टर का लोन लिया था, भर नहीं पाया तो उसने सुसाइड किया। यह प्रमुखता से अखबार में आया है। वहीं पर अगर देखा जाए तो आज भारत के अदंर 70 से 75 प्रतिशत किसान कृषि पर निर्भर हैं। हमारी 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और भारत की कृषि व्यवस्था पर ही आर्थिक व्यवस्था डिपेंड है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बाद कई बार इस सदन में चर्चा हुई है। तमाम माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की है। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट कही गई कि कम से कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाए और यही नहीं जो कृषि स्थायी समिति है, उसने दो बार सिफारिश की है कि 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाए लेकिन उसका भी अनुपालन नहीं हुआ। अभी बात हमारे सम्मानित सदस्यों ने कही है। आज पूरे देश के अंदर और खासकर उत्तर भारत इस समय सूखे की चपेट में है। आज जो रिपोर्ट आई है कि अभी तक पूरे देश में 38.14 लाख हेक्टेअर धान की रुपाई हो पाई है। जो पिछले वर्ष से कम से कम 13.66 लाख हेक्टेअर कम है। बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। बजट में बात कही गई है कि 3 रुपये प्रति दर के हिसाब से 25 कि.ग्रा. गेहूं और चावल देने की बात कही गई है। जहां तक तिलहन की बात अगर देखें तो आधी से भी कम तिलहन की बबाई हो पाई है। मोटे अनाज की बात अगर की जाए तो पिछले वर्ष 56.54 लाख हेक्टेअर की तुलना में 26.6 लाख हेक्टेअर बोया गया जो 30 लाख हेक्टेअर कम है। आपने घंटी बजा दी है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I do not mind to allow you but then other Members of your Party may not get time. Please keep it in mind.

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** सर, हम यहीं समाप्त करके बैठ जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो सर्वे आया, उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत का हृदय प्रदेश है, वह सूखे की चपेट में है। 54 जिलों से सूखे की रिपोर्ट आ चुकी है। 13 जिलों में तो बारिश ही नहीं हुई है। जहां तक अभी खाद्य प्रसंस्करण की बात कही गई है, आज भी चाहे वह सब्जी हो, या फल हो या फूल हो, उसके उत्पादन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जहां तक अनाज की पैदावार अगर देखी जाए तो प्रति वर्ष जिस हिसाब से मानसून है, उस हिसाब से 3 से 4 प्रतिशत आज अनाज की पैदावार घट रही है। हमारी जमीन भी सिकुड़ रही है। आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उस पर बजट में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है कि कैसे आबादी पर नियंत्रण किया जाए। दूसरी तरफ भुखमरी फैली हुई है और जल का संकट भी है। जहां तक किसानी के क्षेत्र में जो रिसर्च की बात कही जाती है, तमाम अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन जो अनुसंधान रिसर्च सेंटर हैं, चाहे एडीआरएफ हो या आईसीआर केन्द्र हो, वे जब अपना पैसा पर्याप्त रूप में मांगते हैं कि हम इस पर रिसर्च करेंगे तो उनको बजट में पैसा भी नहीं मिल पाता जिसके कारण वे कृषि का उत्पादन बढ़ाने में अक्षम हैं। आज देखा जाए तो पूरे देश के अंदर सिंचाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। आज आधी से ज्यादा असिंचित जमीन पड़ी हुई है जिन पर हम सिंचाई की कोई व्यवस्था नही कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कोआपरेटिव सैक्टर की ओर देखें तो खासकर किसानों से यह डाइरेक्ट जुड़ा हुआ सवाल है। सहकारिया की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जहां तक फूड प्रोसैसिंग के लिए बात कही गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं है, बजट में भी बहुत कम प्रावधान किया गया है। यदि अपने देश में देखा जाए तो आज भी 50 हजार करोड़ रुपये चाहे वह

फल हो, सब्जी हो, मांस या मछली हो, वे सड़ जाते हैं। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उनको संरक्षित करके रख सकें।

ब्राजील या और छोटे देश 60 से 80 प्रतिशत संरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे देश में इस तरह की फूड प्रॉसेसिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मेरे ख्याल से भारत में केवल दो से तीन प्रतिशत संरक्षित रख पाते हैं, बाकी सब सड़ जाता है। आज देश में गरीबी बढ़ी है और रोजगार के अवसर घटे हैं। ऐसा नहीं है कि नरेगा योजना चल गई है तो सबको रोजगार मिल जाएगा। हमें इस तरफ सोचना होगा। खास तौर से उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड की स्थिति के बारे में सम्मानित सदस्यों ने जोरदार तरीके से शून्य काल में बात उठाई और सदन का बहिर्गमन भी किया है। यह सोचने की बात है कि कौन सी देश में जगह हैं, जहां सूखे की स्थिति है, वहां विशेष ध्यान देकर पैकेज देने की बात होनी चाहिए।

महोदय, बीपीएल के बारे में भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि बीपीएल का सही स्वरूप क्या है? हम कैसे इसे परिभाषित कर सकते हैं? माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने भी यह बात कही है। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, वहां तमाम लोग घेर लेते हैं और कहते हैं - साहब हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें यह नहीं मिल रहा है, हमें वह नहीं मिल रहा है। चाहे स्थानीय सरकार हो या राज्य की अन्य सरकार हो, उन्होंने सूची दी है कि बीपीएल को ही लाभ पहुंचाना है। लेकिन बीपीएल की स्थिति से भी बदतर स्थिति तमाम गांवों में है। आज बीपीएल को परिभाषित करने की जरूरत है। बीपीएल की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। यहां आंकड़ों के स्वरूप में तमाम बातें रखी गई हैं।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के बारे कहना चाहता हूं कि सौ करोड़ की व्यवस्था की गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से क्या रखेंगे? उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर गांव योजना चलाई गई है। आप किसी भी गांव में चले जाइए जहां अम्बेडकर योजना चल रही है, ठीक है, वहां नाली,खड़ंजा, सड़क के थोड़े बहुत काम हुए हैं। लेकिन अम्बेडकर गांव योजना के अलावा तमाम ऐसे गांव हैं, जिनके बारे में परिभाषित किया गया है कि जहां 45-50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग होंगे, वहां विकास किया जाए। लेकिन जहां 35-45 प्रतिशत लोग हैं, वहां की क्या व्यवस्था होगी? इसे परिभाषित करना पड़ेगा। देश में कृषि नवीनीकरण ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 115 जिले चयनित किए गए हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि बजट में क्या व्यवस्था की है और सरकार क्या करने जा रही है? राजीव गांधी शहरी आवास योजना की बात कही गई है। शहरों में स्लम बस्तियों की हालत आज भी बहुत बदतर है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से इलाहाबाद के लिए जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना की बात कही गई है लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हो पाया है। जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना जिस शख्सियत के नाम से है, यह उन्हीं का नगर है। मैंने कहीं-कहीं देखा है कि कांशीराम शहरी नवीनीकरण योजना भी है, हो सकता है कि पैसा वही हो और नाम बदल दिया गया हो। इस तरह की व्यवस्था को भी देखने की जरूरत है। जिन गरीब लोंगों के सिर पर छत नहीं है, मैं चाहता हूं कि उनके लिए छत की व्यवस्था की जाए। आपने इनके लिए 5000 रुपए बढ़ा देते हैं और 25,000 से 30,000 रुपए देते हैं। एक गरीब अपने घर में एक बरामदा और कमरा बनाता है जो अब 25,000 रुपए में बनने वाला नहीं है। आपको आज के समय में कम से कम 50,000 रुपए की व्यवस्था करनी होगी तब जाकर एक कमरा और बरामदा बन सकता है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने अल्पसंख्यक कल्याण योजना की बात कही है। अभी माननीय मंत्री जी बैठे थे लेकिन अब चले गए हैं। आज भी अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की स्थिति बहुत बदतर खराब है इनेके सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक आधार को मजबूत करने की बात है। यह ठीक है कि आरक्षण की बात कही गई है लेकिन ऐसी बहुत सी रिक्तियां हैं जो भरी नहीं जा रही हैं, उनकी उपेक्षा करके जनरल कैटेगिरी से भरी जा रही हैं। आज भी उनकी माली हालत बहुत खराब है। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी आवास योजना के नाम पर पीडी साहब, प्रतापगढ़ ने 2008 में ही 17 ब्लाकों में धन उगाही का काम किया लेकिन आज तक किसी को कहीं भी आवास नहीं मिला। जब वहां के सीडीओ और डीएम ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही तब पता चला कि सीडीओ और डीएम का ट्रांसफर हो गया। इस तरह से बहुत बड़ा घोटाला देश में हो रहा है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि किस तरह से भ्रष्टाचार मिटाया जाए। भ्रष्टचार नीचे से नहीं है ऊपर से है। आज भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जब ऊपर से हथौड़ा चलेगा तब जाकर नीचे सुधार आ पाएगा और सही लाभार्थियों को फायदा मिल पाएगा।

इन्हीं बातों के साथ चूंकि समय की कमी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सभी सांसदों के क्षेत्र में टाउन एरियाज हैं, जिनमें कस्बे के रूप में लगभग 30-40 या 45 हजार की आबादी है। वहां बी.आर.जी.एस. योजना के अंतर्गत एक टाउन एरिया को आप पांच करोड़ रुपये दे रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम टाउन एरियाज की उपेक्षा हो रही है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो बजट बनाकर निचले स्तर पर भेज रहे हैं, वह सब जगह जाए, सबको वितरित हो। इसके बाद बी.पी.एल. की गरीबी हटाने की बात कही जाती है। मैं समझता हूं कि उन्हें तभी फायदा होगा, जब उनके खाते में डायरेक्ट पैसे जाएं। 'नरेगा' में आपने चैक की व्यवस्था की है। जब तक आदमी एक हफ्ते में बैंक से चैक कैश करायेगा, तब तक उसका परिवार भुखमरी का शिकार हो जायेगा। इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कम से कम जो गरीब लाभार्थी हैं, उन सबको इसका डायरेक्ट फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, आज सम्मानित सांसदों की उपेक्षा हो रही है। मंत्री जी खड़े होकर जवाब दे देते हैं कि निगरानी सतर्कता समिति बनी है, उसमें आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन आज सांसदों की स्थिति यह है कि कहीं भी, किसी भी जगह, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो या शासन से संबंधित अधिकारी हो, उस पर किसी सांसद का कोई अंकुश नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि जो बजट में प्रावधान हुआ है, वह सही लोगों तक जाए और उसकी निगरानी में तमाम जवाबदेही सांसद, विधायक, बी.डी.सी.के प्रधान, ब्लाक प्रमुख और सदस्य, जिला पंचायत आदि की बनती है। आप इनकी जवाबदेही सुनिश्चित कीजिए, इन्हें अधिकार दीजिए। तभी आपकी परियोजनाएं सार्थक हो पायेंगी और लोगों को फायदा मिलेगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):** सभापति महोदय, आपने मुझे बजट (सामान्य) की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शायद पहली बार देश में ऐसा बजट पेश हुआ है, जिस पर लोगों में कोई जिज्ञासा, कोई चाह और कोई खुशी नहीं है और मैं कह सकता हूं कि यूपीए सरकार जब आम जनता के बीच में गई थी तो लुभावने नारों के साथ गई थी। लेकिन सत्ता में लौटने के बाद जनता के लिए जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया, उससे आम जनता को बड़ी निराशा हुई है। इसमें सच्चाई कम है और आंकड़ों की बाजीगरी ज्यादा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह बजट निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक है। क्योंकि इस बजट में किसानों, व्यापारी, बुनकर, बेरोजगार नौजवान आदि सब लोगों की अनदेखी की गई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह बजट दिशाहीन और जनविरोधी है। इस बजट में सामाजिक क्षेत्रों की अनदेखी की गई है तथा गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के विकास के लिए कोई प्रभावशाली ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। इस बजट में हथकरघा बुनकरों के लिए स्थापित किये जाने वाले क्लस्टर को स्थापित करने की बात तो कही गई है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं है। हमारे प्रदेश को इससे वंचित रखा गया है। वहां पर अल्पसंख्यक और एस.सी.,एस.टी. के बुनकर काफी तादाद में हैं। इस बजट में हैंडलूम सैक्टर की भी उपेक्षा की गई है तथा हाथ से इस्तेमाल करने वाला जो कॉटन यार्न होता है, उस पर आठ प्रतिशत टैक्स लगाकर गरीबों को तबाह करने की साजिश की गई है और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने और फायदा पहुंचाने का काम किया गया है।

मैं समझता हूं कि बजट में तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन पर टैक्स हॉलिडे की सुविधा का लाभ चुनिंदा उत्पादकों को पहुंचाने की गरज से किया गया है। प्रणब दा एक जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। बजट पेश करने से पहले आम जनता को भरोसा था कि यह बजट गरीब किसानों और नौजवानों या ऐसे पिछड़े समाज के हित में होगा लेकिन बजट देखने के बाद पूरे देश को यह संदेश गया कि यह बजट आम जनता के लिये नहीं बल्कि देश में पूंजीपतियों के हित के लिये लाया गया है। कांग्रेस ने नारा दिया था कि कांग्रेस का हाथ, गरीबों के साथ। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का यह हाथ पूंजीपतियो के लिये है। इसलिये मैं इस बजट को देश को गुमराह करना वाला बजट कह सकता हूं ।

सभापति जी, पिछली यू.पी.ए. सरकार ने 7 जून, 2008 को पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ाये। जब चुनावी वर्ष 2009 आने वाला था तो जनवरी, 2009 में सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के दाम फिर घटा दिये। केवल सैंसैक्स के आंकड़े देखकर इस देश की गरीबी और अमीरी को नापना गैर-सैद्धांतिक बात है। देश की भोली-भाली जनता को गुमराह करने के लिये पेट्रोल और डीज़ल के दाम घटा दिये। जनता बहकावे में आ गई। जब यू.पी.ए. सत्ता में आयी तो पूंजीपतियों के चंगुल में फंसी सरकार ने संसद का सत्र शुरु होने से ठीक 11 घंटे पहले उसने पेट्रोल और डीज़ल के दाम संसद को विश्वास में लिये बिना ही बढ़ाकर देश के गरीबों पर महंगाई का चाबुक चलाने का काम किया। मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहिन मायावती को बधाई दूंगा कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों से महंगाई से त्रस्त आम आदमी को महंगाई की मार से बचाने के लिये पेट्रोल और डीज़ल पर टैक्स न लगाकर प्रदेश की जनता को राहत देने का साहसिक कदम उठाया। मैं उसका स्वागत करता हूं।

सभापति जी, मैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि देश के 44 हजार गांवों की इस बजट में चर्चा की गई है। जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा एस.सी.एस.टी. के लोग रहते हैं, उनके बेहतर विकास के लिये यह कार्यक्रम बनाया गया है। उसमें महज 100 ग्रामों के विकास की बात कही गई है। इसके लिये केवल 100 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। मैं उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा कि जहां एस.सी.एस.टी. बाहुल्य गांवों का सम्पूर्ण विकास करने के लिये काफी पैसा खर्च किया गया है। मैं जानता हूं कि हमारे मित्र उसकी चर्चा कर रहे थे। ऐसा नहीं कि केवल अम्बेडकर गावों - जहां एस. सी.एस.टी. के लोग रहते हैं, उन का विकास किया जाना है बल्कि जहां सामान्य जाति या ओ.बी.सी. के लोग रहते हैं, उन गांवों का समग्र विकास किया जाना है। उनके विकास के लिये कहीं कहीं 80 लाख रुपया और कहीं कहीं तो दो-ढाई करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्र के 10 लाख रुपये से गांव का कौन सा विकास हो पायेगा?

सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की बात की है लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समाज में जहां एस.सी.एस.टी.या ओ.बी.सी. या सामान्य वर्ग के गरीब लोग रहते हैं, उनके विकास के लिये कोई कार्यक्रम बनाने का आश्वासन इस बजट में नहीं दिया गया है।

काफी दिनों से संसद में यह मांग होती रही है कि एससी, एसटी और ओबीसी कोटे को पूरा किया जाए, लेकिन इसके लिए बजट में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इस देश मैं 60-65 फीसदी से ज्यादा किसान हैं और उनकी बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गये हैं। किसानों को सस्ती दर पर बिजली, खाद उपलब्ध कराने के लिए, सस्ते दर पर किसानों को यंत्र उपलब्ध कराने के लिए, किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश में जो गरीब लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है और वे आज असहाय की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों का जीवन बचाने के लिए भी इस देश की सरकार ने अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हर साल देश के एक बहुत बड़े भू-भाग में बाढ़ की तबाही से बहुत नुकसान होता है। इस बजट में उस बाढ़ की तबाही से देश को बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यूपीए सरकार नरेगा पर अपनी पीठ खूब थपथपा रही है और इस पर इन्होनें काफी चर्चा की है। सरकार कहती है कि हमने नरेगा में 144 परसेंट बजट बढ़ा दिया है। मैं कहता हूं कि यह बाजीगरी का आंकड़ा है और इसमें जल संसाधन से लेकर फॉरेस्ट और ग्रामीण सड़क का सारा बजट इंक्लूड कर दिया गया है। सब यह कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम किया है। इन्होनें इसमें लिखा है कि नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को 100 रूपए मजदूरी देने के लिए केंद्र सरकार वचनबद्ध है। ऐसा करके ये सोच रहे हैं कि इन्होंने मजदूरों को बहुत बड़ी चीज दे दी है। जब से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है तब से ही, दो साल पहले ही बहन कुमारी मायावती जी ने यह घोषणा की थी कि प्रदेश में गरीब मजदूरों को 100 रूपए मजदूरी दी जाएगी और यह दी भी जा रही है।

महोदय, केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर संतरी तक सारे लोग नरेगा पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि इस देश में एक

परिवार को साल भर में 6 से लेकर 8 सिलेंडर दिये जाएंगे। यह आश्वासन निश्चित रूप से अव्यवहारिक है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर हमारे वित्त मंत्री जी और यूपीए की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं, हम गरीब इलाके से आते हैं कि ब्रांडेड ऑर्नामेंट्स पर छूट दी गयी है। हम यह जानते हैं कि मेट्रोपोलिटन सिटी में जो गरीब लोग रहते हैं, जो गांव, देहात में झोपड़ियों में रहतें हैं, वे बड़े-बड़े मॉल में नहीं जा सकते हैं। उन्होंने तो मॉल देखा भी नहीं है कि वह कैसा होता है, उन लोगों ने तो मॉल का नाम तक नहीं सुना है। यहां पर बैठे बहुत से माननीय सदस्यों ने भी मॉल नहीं देखा होगा, जहां ब्रांडेड ऑर्नामेंट्स होते हैं। बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की गरज से सोने, चांदी पर शुल्क बढ़ाया गया है। गरीब आदमी तो छोटी सुनार की दुकान पर जाता है और मात्र 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार, या 10 हजार के गहने खरीदता है। आपने इससे गरीब को निराश किया है और उनके साथ धोखाधड़ी की है।

महोदय, बीपीएल की सूची वर्ष 2002 में तैयार की गयी थी। मैं समझता हूं कि इस हाउस में बैठे सभी सांसद इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए। जहां भी हम लोग जाते हैं वहां लोग कहते हैं कि हमारे पास लाल कार्ड नहीं है या बीपीएल की सूची में हमारा नाम नहीं है। इस बात पर पूरा हाउस एकमत हैं कि बीपीएल सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए और बीपीएल सूची में आने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। इस बात का जिक्र इस बजट में नहीं हुआ है।

महोदय, नौजवानों के लिए भी बहुत कुछ करने का इस बजट में आश्वासन दिया है। देश में नौजवानों को नौकरी देने के लिए आपने कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। इस ओर मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महिला आरक्षण की बात कई बार आई। इस बजट में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई सार्थक और साहसिक कदम नहीं उठाया गया। इस देश की संसद में कई बार कन्या भ्रूण हत्या रोकने की बात कही गई, लेकिन कभी भी संसद में इसके लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने गरीब बालिकाओं की शिक्षा के लिए, चाहे वे समाज के किसी भी तबके की हों, अपने शासनकाल में प्रोत्साहन स्वरूप 25000 रुपये और एक साइकिल देने का काम किया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किया गया कि जिस घर में बच्ची पैदा होगी, उसी दिन उसके नाम से 20 हज़ार रुपये जमा कर दिये जाएंगे और जब 18 साल की वह बच्ची होगी तो एक लाख रुपये उसे दिये जाएँगे। इस योजना से कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सकता था, लेकिन इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अलावा मैं शहरों में श्रमिकों की बात करना चाहता हूँ। जब से देश आज़ाद हुआ, तब से पहली बार शहरों में गरीबों के आवास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसी योजना के नाम पर, इंदिरा आवास या जिस नाम पर 20000 रुपये मिलता था, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे दो कमरे और लैट्रीन बाथ सहित उसको आवास बनाने की योजना दी। अब तक उनके साथ मज़ाक होता रहा। शहरों में गरीबों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने शहरों में गरीबों के रहने के लिए कांशीराम साहब के नाम से, जिन्होंने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए इस देश में एक संदेश दिया, उनके नाम पर गरीबों को आवास देने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो बजट पेश किया गया है, निश्चित रूप से यह निराशाजनक है, इसके बावजूद भी मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, the name of our party's Member is at number four. I think, it should be our party's turn now.

MR. CHAIRMAN : Next will be the turn of your party's Member.

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर):** सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। लोक सभा के आम चुनाव के बाद जब केन्द्र में यूपीए की सरकार बनी और बहुत लंबी चर्चा के बाद जब प्रणब दा वित्त मंत्रालय में आए तो पूरे देश के लोगों में यह आम चर्चा थी कि प्रणब दा का जो लंबा अनुभव रहा है वित्त मंत्रालय और सरकार में कामकाज करने का, उसका लाभ इस देश को मिलेगा और इस बार का जो बजट है, वह आम लोगों को राहत पहुँचाने वाला होगा। लेकिन जब बजट पेश हुआ, और बजट पेश होने के बाद आज की तारीख में भले सरकार को यह अहसास नहीं है, लेकिन हर चौक-चौराहे पर, सड़क पर, गली में और गाँव में इस बात की चर्चा है कि इस बजट ने पूरे देश का भट्ठा बैठाने का काम किया है। सरकार ने जो बजट पेश किया है, 10,20,838 करोड़ रुपये का, उसमें 6,14,497 करोड़ रुपया इन्होंने दिखाया है कि राजस्व से आएगा और 4,06,341 करोड़ रुपये इन्होंने ऋण से दिखाया है कि मार्केट बॉरोइंग से आएगा। पिछली बार का 2008-09 का बजट अगर हम देखें और उस बजट में इनका जो वास्तविक आकलन था, बजट अनुमान था, वह था 1,40,724 करोड़ रुपये ऋण का, और जब वास्तव में वह आया तो 3,08,796 करोड़ रुपये आया।

अगर यही रफ्तार इनकी मार्किट बोरोइंग की है, तो इस साल के बजट में इन्होंने 406341 करोड़ रुपयों के ऋण की बात कही है, यह बढ़ कर 12 लाख करोड़ पर जाएगा। आप देश को कहां ले जा रहे हैं? आपने बहुत ढिंढोरा पीटा है कि कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत क्रांति लाए हैं, इन्होंने क्या किया है? इनका जो प्लान आउट-ले है, उसमें कृषि के क्षेत्र में मात्र 10629 करोड़ रुपया दिया है। 1020838 करोड़ रुपए के बजट में सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपया कृषि क्षेत्र में दिया है। एक प्रतिशत कृषि सैक्टर में दे कर इन्होंने क्रांति लाने की बात कही है। हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारे 75-80 परसेंट लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। बेरोजगारी को यदि दूर करना चाहते हैं, तो आपको कृषि पर केन्द्रित करना होगा।

महोदय, यूपीए की सरकार ने पांच वर्षों के बजट औद्योगिक उत्पादन को केन्द्रित करके बनाए हैं। उसी का परिणाम है कि आज देश कहां पहुंच चुका है और आप आगे देश को कहां ले जाना चाहते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने गैस के बारे में अपने बजट में जरूर कहा है। गैस एक ऐसा महत्वपूर्ण कम्पोनेंट है जिसकी आवश्यकता हमारे औद्योगिक उत्पादन, बिजली उत्पादन और खाद के उत्पादन के लिए होती है। इन्टरनेशनल स्टैन्डर्ड पर कम्पीट करने के लिए गैस उत्पादन सबसे चीपैस्ट माध्यम है। गैस के उत्पादन पर मंत्री जी एक पॉलिसी बजट भाषण में लेकर आए हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम वित्त मंत्री जी से यह उम्मीद करते हैं कि वह उसे शीघ्र लागू करेंगे और कार्यान्वित करेंगे। ईस्टर्न क्षेत्र, जो कि गैस की पहुंच से अछूता

है, वहां भी गैस पहुंचाने का काम करेंगे।

महोदय, अब मैं अपनी पूरी बात अपने प्रदेश की ओर केन्द्रित करना चाहूंगा। आप यह कह रहे हैं कि हम अगले 15 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करेंगे। हमारा बिहार प्रदेश दस करोड़ की आबादी वाला है। दस करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को निगलैक्ट करके आप किस प्रकार से विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, यह हमारी समझ से बाहर है।

महोदय, मैं चाहूंगा कि आप वर्ष 2004 और वर्ष 2005 का बजट भाषण देखिए। उस समय चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे। उस समय उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। वर्ष 2004 में जब चिदम्बरम साहब ने पहला बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने इसी सदन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने वर्ष 2005 में रीपीट भी किया था। लेकिन आज हमारा स्पेशल पैकेज कहां चला गया है? आपने कितने रूपये का स्पेशल पैकेज हमें दिया है? हमारा प्रदेश कृषि पर आधारित है। वह बाढ़ और सूखाढ़ से प्रभावित है, लेकिन आप हमें एक रूपया भी अनुदान नहीं दे रहे हैं। हमारे आंतरिक संसाधन सीमित हैं। हम किस पर निर्भर करें। बंगाल में आइला आया, आपने उसके लिए एक हजार करोड़ रूपया दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप पांच सौ करोड़ रूपये दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने मुंबई को दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोसी में बाढ़ आयी, जिसके कारण लाखों लोग बेघर हो गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां गए, उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय आपदा है, हम इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं। वह राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कहां चली गई? आपने एक रूपया भी नहीं दिया। वहां के खेतों में बालू और मिट्टी भर गई। राज्य सरकार ने लोगों के पुनर्वास और रहने की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव दिया। लेकिन आप उस पर सोए हुए हैं। एक रूपये की भी घोषणा आपने बजट भाषण में नहीं की है। आप किस प्रकार का बजट लाना चाहते हैं?

महोदय, सरकार माइनोरिटी की बात करती है। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी की ब्रांच खोलने की बात आपने बजट भाषण में कही है। +

राज्य सरकार ने कहा कि किशनगंज में आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोलिए, हम उसके लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं। आप क्यों नहीं आगे आए, क्यों नहीं आपने उसे वहां खोलने का काम किया? आपने कहा कि हैंडलूम और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करेंगे। हमारा भागलपुर सिल्क के मामले में एक समय में पूरे विश्व में विख्यात था। आज भागलपुर का सिल्क उद्योग मृतप्राय है। वहां छोटे बुनकर और हैंडलूम कलस्टर है, आपने भागलपुर में खोलने की बात क्यों नहीं की? वह पिछड़ा प्रदेश है, आप उसे क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं? आप वहां के लिए स्पेशल पैकेज नहीं दे रहे, आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं। आपकी नीयत में खोट है। पांच वर्षों की बात हम समझ सकते हैं, आपने इतने वर्षों में क्या किया, हम समझ सकते हैं। प्रजातंत्र में किसी को ताकत मिलती है, प्रजा अगर किसी को ताकत देती है तो उस ताकत का इस्तेमाल लोग राज्य हित में करते हैं। यहां पिछले पांच वर्षों में उस ताकत का इस्तेमाल राज्य को बर्बाद करने में किया गया। राज्य की विकास योजनाओं को रोकने में किया गया।

सभापति महोदय, बिहार की जनता ने इन्हें सजा दे दी है। प्रजातंत्र में जनता मालिक है। लोग जितना भी समझें, लेकिन प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है। वह सब देखती रहती है, उन्होंने इन्हें सजा दे दी। अब आपको क्या हुआ, आप उस दबाव से क्यों नहीं मुक्त हो रहे हैं? आप बिहार के साथ न्याय क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप बिहार का हक उन्हें क्यों नहीं देना चाहते हैं? हमारा उद्योग इथनोल, सामान्य बजट से उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा के लिए हम यहां कहना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा, उन्होंने हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आज जो पैट्रोलियम की स्थिति पूरे विश्व में है, उसके लिए इथनोल के उत्पादन को बढ़ावा दीजिए। जिस दिन प्रधान मंत्री जी का पत्र राज्य में पहुंचता है, उसके दूसरे दिन कृषि मंत्रालय और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन पहुंचता है कि जब तक चीनी का उत्पादन नहीं होगा, तब तक इथनोल का उत्पादन नहीं हो सकता है। अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है, वह चीनी या इथनोल का उद्योग लगाए, उसे आप क्यों रोकना चाहते हैं? यह साबित करता है कि आप बिहार और उस प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहते हैं। आप विकास को बाधित कर रहे हैं, आप यह काम दबाव में कर रहे थे, इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में आप पर कोई दबाव नहीं है। आज की तारीख में अगर आपको जनता के बीच में बिहार में जाना है तो बिहार का जो हक, हिस्सा एवं हुकूक है, उसे आपको बिहार को देना होगा और अगर बिहार को ये सब नहीं देंगे तो बिहार के लोग उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप जब बजट में उत्तर देंगे, आपने जो बिहार की उपेक्षा की है, उस उपेक्षा का आप उत्तर यहां अपने वक्तव्य में देंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हम दो बिन्दुओं पर सिर्फ एक-एक मिनट चर्चा करना चाहते हैं। यहां नरेगा की बात हुई है। नरेगा पूरे देश में चला, कुछ लोग घूम-घूम कर अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि नरेगा में हमने तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने नरेगा में क्या तूफान खड़ा कर दिया, मैं चुनौती देता हूं कि किसी भी इनडिपेंडेंट एजेंसी को अगर इसकी समीक्षा करने के लिए, पूरे देश में इसका सर्वे करने के लिए भेज दीजिए, उससे फ्लॉप स्कीम आज तक कोई साबित नहीं हुई, उससे ज्यादा लूट का कोई जरिया साबित नहीं हुआ। लूट का जरिया खोल कर लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये अपने आपको बड़ा तीसमारखा साबित करना चाहते हैं। उन्हें छूट है, वे करें, लेकिन धरातल में स्थिति यही है।

सभापति महोदय, बीपीएल की चर्चा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक फैसला हुआ था, कि डोर टू डोर सर्वे करके सर्वेक्षण किया जाएगा। अंक निर्धारित किए गए और उस अंक के आधार पर घर-घर जाकर सर्वेक्षण हुआ। हमारे प्रदेश में एक करोड़ पैंतीस लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। भारत सरकार कहती है कि मेरा संपूर्ण सर्वे कहता है कि 65 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, बाकी जो 35 और 85 लाख परिवार का गेप है, वह कहां से पूरा होगा। इस तरह से आंकड़ों के बल पर केन्द्र की सरकार साबित करना चाहती है कि गरीबी मिट गई।

यह साबित करना चाहते हैं, यह इस बात का प्रमाण है। अगर गरीबी मिटाने का आपका यही मापदण्ड है तो अगले 10 वर्षों में क्या, अगले 100 वर्षों में भी देश से गरीबी नहीं मिटा सकते हैं।

यही कहकर हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Hon. Chairman, Sir, I extend heartfelt gratitude on behalf of my Party, my people and

myself for allowing me, to express my opinion and draw the attention of the hon. Members of this citadel of democracy as I rise to support the General Budget of the year 2009-2010 presented by the hon. Finance Minister Shri Pranab Mukherjee.

Through yourself, respected Sir, I wish to felicitate the hon. Finance Minister's effort to facilitate domestic demand-driven growth, trying to create newer job opportunities and reach out to rural and urban poor. To do so, I feel, allocation of more funds to the Railways is necessary.

As far as food security is concerned, the National Food Security Act is being carried out in all earnest to provide grains to BPL families at Rs.3 per kilogram for 25 kilograms of grain per month. This will curb hunger no doubt, but will it maintain health, prevent kwashiorkor marasmus? At the United Nations Millennium Summit, 189 member States of United Nations General Assembly including our very own India committed to reduce poverty, improve health, promote peace, and promote human rights and environmental stability. The Millennium Development Goals drawn from the Millennium Declaration thereof thus signed and set out eight goals and quantifiable time-bound targets to reduce poverty, hunger, ill health, gender inequality, improve access to education, clean water and environment for all by the year 2015.

While subsequently our country has progressed no doubt on many development markers, chronic hunger related malnutrition and compromised chronic health related situations persist even today. Every one out of two children and every one out of three adult women suffer from malnutrition. Every three out of four children and one out of two women suffer from anaemia in the population, amongst pregnant women this is much higher. Malnutrition contributes to over fifty per cent child death. A child born of a mother of compromised health is more prone to disease and death and so is the mother. To reach the target of reducing maternal mortality, infant and child mortality, the supply of grain, as suggested at Rs.3 for 25 kilograms a month is not enough. The other nutritional requirements like vitamins, minerals and regulated amounts of proteins and fats will have to be ensured through the PDS and awareness towards this end initiated. I thus request the hon. Finance Minister to consider fortifying grains and supply such elements to effectively reach the said targets.

I would like to draw your attention to delivery of potable drinking water, that is, arsenic free. You must be aware in this august House that arsenic poisoning is like an epidemic in the State of West Bengal from where I come, particularly the district from where I come, the North 24 Parganas, causing cancer and hepatic mal-functions. Thousands of people are dying. Arsenic free water supply projects must be undertaken immediately and funds sanctioned for the purpose.

I congratulate the hon. Finance Minister at his initiative towards skill development and putting vocational training at par with higher studies through exemption under section 80E on educational loans.

The initiative taken by the hon. Finance Minister towards reaching out to greater numbers through NREGS, SGSY, SHG, Rashtriya Mahila Kosh is laudable. But in many States, the employment guarantee has not reached its target like in West Bengal; they could not meet the target. I see no improvement in result output in my constituency and State since the actual poor and the poorest of the poor have not been included.

The work on drawing up of the BPL list in a just manner must be immediately completed and brought before the public to take benefit from the projects drawn up thereof.

I thank the hon. Finance Minister on behalf of the small and marginal taxpayers. Here, however, I would like to humbly place a request to look into the possibility of enhancing the upper limit of personal income-tax exemption of small and marginal taxpayer up to Rs.2.5 lakh per annum, and also request the interest on small savings which poorer and middle income-groups take advantage of .

Hon. Finance Minister has very kindly taken into consideration the health sector. It is definitely encouraging. However, a lot more is expected in the health sector. A nation to progress wisely and effectively has to be healthy because the productivity definitely reduces with an unhealthy nation. It is encouraging to note that nine specified life-saving drugs and devices have received his blessings - though it is not classified in detail. I would like to know whether these include Thrombolytic agents like Strepto Kinase or Alteplase, Gonadotropines and pacemakers, which have to pay a basic five per cent duty, four per cent surcharge, three per cent cess and four per cent Value Added Tax.

Hon. Finance Minister has followed a journey - मृत्यु मां अमृतो गमयो, - an endeavour towards saving life. May I take this opportunity to request to initiate a journey towards light – तमसो मां ज्योर्तिगमयो। May I request him through you, Sir, to peer into the eyes of a childless women, into the depth of darkness and despair in her eyes. When the World Health Organisation has described correctly and completely this disease condition, women in our country are still ostracised, divorced and tortured for their illness. Will they find any justice? Will their human right to procreate be denied? Why are medical insurance facilities denied to them? बांझपन बीमारी है, लेकिन इन्हें डाइन क्यों कहा जाता है? Facility being unavailable in most Government hospitals; two to three million such women suffer every year. Private facilities of world class result have to pay very heavy duties for life-creating devices. We have spoken about life-saving devices in the budget, I draw you attention to life creating ones.

Here I would bring to your attention, the life-creating devices like culture media, in which early human embryos thrive, is taxed at 28 per cent being treated as an ordinary chemicals like kerosene, etc. Carbon dioxide Incubators which are the wombs to such babies are taxed at 28.6 per cent − being treated as poultry ovens. Nowhere in the world, this happens! Other tissue grade plastics, catheters, needles are treated like ordinary plastics like a kerosene jar and charged 28.6 per cent also. All these millions suffering from childlessness requiring Assisted Reproductive Technologies are looking up to you. The result, of the Indian Groups working in these subjects for more than 27 years now, comparable to any developed centre of the world look up, through you, to the Finance Minister for support along with all these millions of people to make this service available to all sections of society since it does not exist in the Government sector, except, as far as my knowledge knows, in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. All sections of the society would avail the facility at a much cheaper rate if this taxation could be taken care of. I voice the request of three million such sufferers to reconsider the duty pattern on these items so that they can also avail the facility that is available today in science throughout the world. The World Health Organisation have always extended support but here in our country, the little babies, the parents of tomorrow being born to childless mothers in the laboratories are treated like poultry chicken. I draw your attention to it.

.

**17.00 hrs.**

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, on behalf of my Party, AIADMK, I rise to participate in the discussion on the General Budget presented by the hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee for the year 2009-10.

We are very happy to note that some of the programmes like '100-day agenda', National Citizen Identity Cards', and other measures like 'abolition of Fringe Benefit Tax, more allocation for police modernization, more funds for Defence and for setting up of more IITs, etc.' which are mentioned in our AIADMK Party's Election Manifesto are included in his Budget Speech and getting implemented.

I expected that the present Finance Minister would come out with some solutions to the problems that the country is facing like agricultural crisis, price rise, joblessness and recession.

This Budget attempts to net some short-term gains by putting more money in tax-payers hands and allocating more funds to infrastructure and social welfare programmes. The absence of a long-term strategy for fiscal consolidation is conspicuous and it is disappointing.

The Budget provides for a total expenditure of Rs.10,20,838 crore consisting of Rs.6,95,689 crore towards Non-Plan and Rs.3,25,149 crore towards Plan Expenditure. The Budget figures show Gross Tax Receipts of Rs.6,41,079 crore, which was Rs.6,87,715 crore in the previous year.

The Non-Plan Expenditure is projected to rise by 37 per cent this year. Interest payment takes lion's share in this, with Rs. 2.25 lakh crore. Borrowing of the Central Govt. is likely to be around Rs. 4 lakh crore, which is an increase of three times over the past year.

The Finance Minister has admitted in his Budget speech that the fiscal deficit will increase to 6.8 per cent of GDP this year from 2.7 per cent in the previous year, which is a clear area of worry. According to the FRBM Act, the Government is duty-bound to reduce the fiscal deficit by 3 per cent of GDP every year. Even to bring down the gap from 6.8 per cent to 5.5 per cent of the GDP in 2010-11 and 4 per cent in the following fiscal, the deficit had to be cut down by Rs. 2.8 lakh crore through higher growth.

Is it achievable or just imagination based on the calculated highest risk, that our Finance Minister said? Nobody is sure whether this calculated risk will pay off in terms of higher growth in the near future. He blamed the global slowdown for this fiscal deficit, but this is not a convincing reason. This fiscal deficit is due to mismanagement of the economy in the past.

The revelation of higher-than-expected fiscal deficit added to the woes. The deficit-number is beyond the market target and Government has to borrow more from the market this year to fund its *aam aadmi* programmes. As the Government competes with the private sector for funds, the Government tends to push up interest rates and crowd out the private sector. This rise in rates finally ends up hindering rather than helping growth. There would not be enough money to fund private investment. This may further delay the revival of the Indian economy.

At Para no. 5 of his speech, he narrated things like 'we need to sustain a growth rate of 9 per cent per annum, strengthen mechanisms for inclusive growth to create about 12 million new jobs per year, reduce the proportion of people living below poverty line, ensuring that agriculture grows at 4 per cent per annum, and we need to move towards providing energy security, etc.'

In the very next paragraph, he had shown pessimistic approach; he said that the Budget cannot solve all these problems. If the Finance Minister of the country is not able to solve these problems, who will solve those problems? He should find ways and means for correcting the financial misdeeds that his Govt. has done over the last few years.

Then, he mentions about three challenges, that is high GDP growth rate of 9 per cent per annum, inclusive development and re-energize Government and improve delivery mechanisms. But he did not mention anything about how he is going to address those challenges. He admits that there has been a dip in the growth of GDP from over 9 per cent to 6.7 per cent this year. It has affected job creation, investments and lowering of revenue. But he has not spelt out anything about how he is going to achieve the growth rate of 9.per cent.

The Government is saying that inflation has come down to record levels. What about inflation of food prices? The prices of essential commodities and consumables like sugar, dal, salt, seasonal vegetables and even matchboxes have increased sharply.

Why the Government did not do anything in the last five years to manage the price line? What happens to the middle class people and the common man? The Government may claim that there is negative inflation, but it is of least concern to the common man. This is a sorry state of affairs and the Government should think seriously about the price rise. The Government has to put a full-stop to the online trading in essential commodities like rice, wheat and pulses, which affects the middle class and *aam admi.*

Internationally, prices of crude and petrol have stabilized, but the Government has increased Indian diesel and petrol prices last week. This drastically increases the input costs of consumables. When the international oil price fell below 50 dollars, this Government did not bring down the Indian oil prices to that level, but when it increases, this Government immediately takes action to increase oil prices.

The Hon. Minister said that agriculture is likely to grow at 4 per cent. But there is inadequate allocation for it to grow at that rate. There is an agrarian crisis in the country. Farmers are committing suicides in huge numbers. In the last 12 years, 1,90,753 farmers have committed suicide in the country.

The renowned Agriculture Scientist, Dr. Swaminathan has given a very clear recommendation that the interest rate on farm loans should be slashed to 4 per cent. But even today the nationalised banks are giving farm loans at the rate of 7 per cent. The Finance Minister has reduced it to 6 per cent, only for those loans ranging up to Rs.3 lakh and that too, only for those who pay on time.

The proposed Task Force, to look into the waiver of loan taken from private money lenders in Maharashtra region, should also look at other regions of the country where such problems exist.

Hence, on behalf of AIADMK, our Hon. Amma had suggested that all existing farm loans including those taken from the non-nationalized commercial banks should be waived off. There has to be subsidy for seeds and fertilizers.

I would like to suggest that there might be a Farmers' Commission, which could fix the remunerative procurement prices.

The Finance Minister may look into the possibility of converting NABARD into a direct financing institution for farmers, to monitor easy flow of funds to them.

The Hon. Finance Minister said in his Budget that the number of BPL families will be brought down to half-the-number and that he would take efforts to provide 25 Kgs. of rice or wheat every month at the rate of Rs.3 a kilo. Though it is a welcome measure, the fund allocation is inadequate.

All over the country, there is rising unemployment, due to economic slowdown. About a year ago, the Prime Minister and the then Finance Minister said that the Indian economy is insulated, that our fundamentals are strong, and that we need not worry. But what has happened? In the last six months, in every sector - be it garments, be it IT, be it construction works, textiles, manufacturing, automobiles - there have been shut downs and lay offs, and they are working with 10 to 20 per cent of their capacity. According to a moderate estimate, more than five million jobs have been lost in the last six months; and there is a possibility of two crore people losing their jobs.

Here, I would mention a word about my constituency. Karur is famous for its textile industries, but it was affected because of many factors, one of them being frequent power cuts. Many shifts in those industries are shut down, leading to widespread unemployment in Karur and adjoining areas. The export of textiles was affected. In Karur, there was a circulation in this industry to the

tune of Rs.3,000 crore per annum, which has come down to Rs. 1,200 crore. This attracts the immediate attention of the Central Government.

Though the Finance Minister has announced many welfare programmes like National Rural Employment Guarantee Act for uplifting the rural people, it is not reaching the intended-persons. State Governments, are not seriously implementing these programmes. The common men are not getting the benefits and the middlemen are exploiting them. I would request the Government to see that the money is properly disbursed to the common men. Unless this is done, the economic and other stimulus measures will not yield any results.

Hence, our Party General-Secretary, Puratchi Thalaivi hon. J Jayalalithaa emphasized the need to revamp the present National Rural Employment Guarantee Act and rename it as the National Rural Upliftment Scheme whereby 75 per cent of the disbursals can be given in kind and the remaining 25 per cent in cash. This will ensure family security and it will prevent wasteful expenditure. The Government can ensure at least 150 days of employment.

On behalf of my Party AIADMK, I feel that the salaried employees are the most sincere taxpayers. I would request that all the salaried employees - both in the Government, and Private - should be exempted from the shackles of income tax and the income tax exemption limit for all others should be increased to Rs. 5 lakh per annum.

Every now and then, the middle class people have some disputes and have to approach some advocates and courts. Now, this attracts 'Service Tax'. Thus, the common men and the people from middle class are affected badly.

I have the following few suggestions for consideration of the hon. Finance Minister.

i) Instructions may be given to banks for giving education loans to the needy students in time.

ii) More allocation may be made for modernising the police force, health sector, energy sector, education etc, which also needs the attention of the Government.

iii) It is an admitted fact that there is 'Rs. 72 lakh crore of Indian money' illegally kept in International Tax Havens. The Finance Minister should make serious efforts to bring back that money at the earliest, as per the demand from our hon. Amma, Puratchi Thalaivi J Jayalalithaa.

iv) Counterfeit currencies, smuggled from neighbouring countries, are in circulation in our country. The Government must take immediate action to control it. Otherwise, our economy is under threat of collapse.

In the wake of the global economic meltdown, the Indian economy has been going through tough times. Tough times call for tough actions and decisions. At this critical juncture, what India needed is an effective, implementable action plan.

As my leader hon. Amma J. Jayalalithaa said:

"In fact, the Finance Minister appears to have not made any attempts to bring the country out of recession. No long-term reforms have been announced. No goals have been fixed. No deadlines have been set. No attempt has been made to control Government expenditure. The entire onus for 'operation resurgence' has been placed on industry with no helping hand from the Government."

The Budget is partially populist, unimaginative and sets no clear roadmap for a better India!

MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Minister for External Affairs will make a statement.

**17.19 hrs.**

**GENERAL BUDGET , 2009-10- GENERAL DISCUSSION**

**AND**

**DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 2006-07 − Contd.**

(Dr. M. Thambidurai i*n the Chair*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, the hon. Finance Minister has presented the General Budget for the year 2009-10. I

think, he has dealt with 137 items excluding his concluding remarks in the Budget. He has tried to touch upon every section. But to analyse the Budget in greater details, it is better to refer to the Economic Survey to get some more data. It shows that the Revenue Deficit has risen to 4.8 per cent. Fiscal Deficit has risen from 2.5 per cent to 6.8 per cent and the growth rate has come down from 9.1 per cent to 6.1 per cent and growth rate on GDP has come down from 9 per cent to 6.7 per cent.

Sir, industrial growth also has shown a decline from 8.5 per cent to 6.7 per cent, electricity generation declined to 3.7 per cent and export growth also declined from 28.9 to 3.6 per cent. Agriculture is the main sector where we see that there is a decline of 4.9 per cent to 1.9 per cent. It is only mining and quarrying where we see some progress. It is really the reflection of global recession that our economy is facing nowadays. I do not blame the Government but it is the global recession also which has hit the Indian economy to a great extent.

As stated by other Members, there is a negative inflation that we are focussing on but I think no one can afford to get any essential goods in any market because the prices of almost all the goods are rising. It is on this basis that we have to think as to how we can tide over the situation that we are facing.

When we see the investment of the Government, it is only two per cent of the GDP in total. It is a very meagre amount. Agriculture is the backbone of the Indian economy. We have made an investment of Rs. 70,000 crore in the last year but we know that there is not much change in the production as far as agriculture is concerned. I do not find any fault with the Government but at the same time, the import policies which you are still continuing is really the result of the bad position of the farmers. The prices of coconut, the prices of arecanut and the prices of pepper are all showing a decline in my State. There is a joke that the price of a coconut is equal to the price of an egg. The price of arecanut was Rs. 160 per kilogram five years back and now, it is only Rs. 40. No one is ready to buy it. The price of other commodities also shows the same figure. In this connection, the Government should try and give more stimulus to agriculture.

Bank credit was Rs. 2,87,000 crores which rose to Rs. 3,25,000 crores. Of course, it is a good figure. But it is bank credit with seven per cent interest. And what about the report of the Swaminathan Committee? The Swaminathan Committee has made clear that the Government should give four per cent interest and also it has made clear that only three-fourth of the farmers are able to go to the banks. So, it does not give any stimulus to the agricultural field.

The other thing which you can do is more investment in irrigation. Of course, there is some increase but at the same time, it is not really adequate for the agricultural field. When we go into the social sector and the details of each sector, we may find crores of rupees of allocation. But we have to see whether it is adequate or not.

The provision to right to education is below Rs. 200 crore. This is true in the case of preliminary education. There is only slight increase of Rs. 200 crore for general education. The Government have announced some scholarships this year. But there is no increase in the number or volume. The Government has also announced the Mid-Day Meal Scheme. I think the then Finance Minister assured the House that the Government is going to extend it to the upper class also. But it is confined to the lower class alone. In many other States, it is extended to the upper classes and they are going ahead to the higher classes also.

This House has passed the Unorganised Workers Bill which is noble. It is really unfortunate to note that there is only Rs. 100 crore of allocation which is very meagre, according to me, for the benefits of the workers because lakhs and lakhs of workers are engaged in the organised sector.

I agree with the Food Security Act which is the need of the people but the budget proposal is disappointing. When many States give 35 kilos of rice at Rs. 2 per kilogram, the Government has taken a decision to give 25 kilos of rice at Rs. 3 per kilogram. It means the quantity has reduced and the price is high. How can you say that it really gives some relief to the common man? It is not the *aam admi* budget.

It is because, what you have done is lesser in comparison to what some States have already done. The Budget has some schemes for minorities, Self-Help Groups, Bharat Nirman, which I really appreciate. But at the same time, there should be some changes in the NREG Scheme. It is really a noble Scheme. But as far as the villages are concerned, some changes should be made with regard to the implementation of the Scheme.

The second task before the Government is mobilising resources. That is the most important issue as far as the Government is concerned. It is true that there is no change in the corporate tax. It is a welcome step. The Government has abolished the Fringe Benefit Tax, Commodities Transaction Tax, and Gift Tax. I think the Government is not ready to touch the upper class people who have earned crores of rupees. In 2007, the number of millionaires in our country was 25. But in 2008 it has gone up to 52. So, you can tax them more because they have the capacity to pay,

As mentioned by other hon. Members, the percentage of malnourished women has gone up to 58 per cent; the percentage of

less-weighed children has gone up to 40 or 48 per cent. So, you need money. You can tax the persons who can bear it. But the Government is not ready to do that. So, the resource mobilisation of the Government wholly depends on the PPP and disinvestment.

In the Budget proposals you have said that 51 per cent shares of the PSUs will be kept with the Government. I cannot understand as to what right you have to sell the rest 49 per cent to the private persons. You have said that it will be sold to the people. But no ordinary person is going to buy any share nor is he going to make any contribution. So, it means that the Government has decided to give the rest of it to the private persons. PSUs are the assets of the people and assets of the nation. You have earlier brought the Insurance Act, the Banking Regulation (Amendment) Act. Now, you are speaking about the Railways, Defence and Coal. So, most of these public shares are going to be given to the private people. It is a very dangerous move.

There is incentive that you give to the other section. That is also a form of tax exemption. Last year, Rs. 4.1 lakh crore were given to private sector. It is a form of tax exemption. Next year also you are going to give this exemption and incentive. It means that within two years, you are giving an exemption of Rs. 8.2 lakh crores. If you use this money, I think, the financial problems of the Government can be solved without much difficulty.

If we see the tax payment of the big companies, I think, only a few companies pay tax. All other companies − I do not want to name them − give very limited tax because of these exemptions in the form of incentives. In the last Lok Sabha we had seen the selling of the 2G spectrum which became a corruption controversy. Now, the Government has decided to sell 3G spectrum at the price of Rs. 35,000 crore. Selling the Government assets has become the day-to-day business of this Government. It is not really a good and healthy economic policy that we can follow. It shows the Government has decided to fill the fiscal deficit of 6.1 per cent by selling the Government assets. This is not a good economic policy. This is just like a farmer selling his land to repay the loans borrowed from the moneylenders. The net result and outcome would be the collapse of the family of that farmer. So, the Government is also going to face the same situation.

The proposal in this Budget to give tax exemption for the donations given to political parties is a dangerous move. It gives power to millionaires to influence the Government. When the millionaires give donations or contributions to a particular political party and when that party comes to power, these persons will have their own say.

So, the Election Commission and the Government also should come out with concrete proposals with regard to the funding of the political parties. The political campaign should be transparent. There should be accountability with regard to that.

With regard to subsidy on fertilizer to be given to the farmers, what the Government has said is not clear. The Government said that the subsidy should be given direct to the farmers. How can it be given? The farmers want fertilizer at a cheaper and affordable price. How can you give money to the farmers, who are the farmers and how will you identify them? So, there should be some clarification in this regard.

The policy of crude oil is also left to the Expert Committee. I strongly protest that when the Parliament was in Session, the Government has increased the prices of petrol and diesel. It was really bypassing the Parliament procedure. It was discussed in this House. So, I do not want to go into details.

Then, I am sorry to say that the State of Kerala is really neglected in this Budget. Though the State is first in education and literacy, the long pending demand of IIT is not sanctioned. In this House and also outside the House, the hon. Prime Minister himself had promised that if the Government takes any decision to give more IITs, of course, Kerala should be given priority. However, it has not materialised so far. I would request the Government to consider this demand.

Likewise, Cochin metro is also very important with regard to the industrial development. Cochin is the centre of industrial sector and it has very cross relation with Mumbai. But nothing has been mentioned about the Cochin metro and no money is sanctioned.

As you know, Kerala has traditional industries like coir, cashew, handloom, beedi etc. which are facing steep difficulties because of the global recession. A large number of people are dependent on this sector. But no special scheme or project is included in this regard.

Sir, every year the Government of India receives at least nine billion dollar from NRIs and 80 to 85 per cent of it is from Keralites because they are going to work there. But as a result of the global recession, a large number of people are losing their jobs and no project is included in this regard. As far as the Kerala Government is concerned, they have made a special packaged scheme for the rehabilitation of the NRIs who are losing their jobs. I think, the Government should take note of this and should make a rehabilitation scheme because they are losing their jobs. They have given a lot of money to our country.

I welcome the Centrally sponsored schemes which really assist the State Governments for infrastructure development and also the social sectors. But considering the complexity of various states and various forms, the geographical features that we see, the growth rate either in the education or in other sectors vary. So, there should be some flexibility in the implementation of the schemes. It is true

that the funds should be used for the schemes which are the Central Government projects. But, at the same time, this flexibility is essential.

Sir, we have a better medical system in Kerala. But, at the same time, new diseases like cancer, HIV, chikungunya are spreading. So, the Kerala Government has requested to give for more assistance with regard to the medical sector also.

Sir, the law and order is really a State subject. But we know, especially in the wake of Mumbai attack of the terrorists and also the terrorism which is spreading in many places, it is essential to modernize the police force. ...(*Interruptions*) So, the introduction of new equipment is most important.

MR. CHAIRMAN : Please wind up. There are some more Members from your Party who want to participate in the discussion.

...(*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, I will conclude with only one point.

Sir, the Government has given an answer in the House that our food production is better and there is buffer stock. Due to various reasons, the Central Government has reduced the food quota of many States and one among them drastically affected is Kerala. There was a reduction of 82 per cent as compared to 2007. So, I would request the Government to consider it and retain the earlier food quota with immediate affect.

Sir, with these words, I conclude my speech.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this chance to speak on the General Budget. I rise here to deliberate on the Budget 2009-10.

The Budget presented by the hon. Finance Minister Shri Pranab Mukherjee is a bit of a surprise. There was talk in the Budget Speech of privatization of the State-owned assets, mentioned as "people's participation" in the public sector undertakings but there is no estimate of the likely earnings incorporated in the projected receipts of the Government. On the other side, those looking for relief for the common people and fulfillment are also very much disappointed. The allocations provided for in this Budget for the social sector and flagship programmes are also so low as to suggest lack of seriousness on the part of the Government in meeting its own stated objectives.

It is often said that the Budget has to be assessed in terms of five Ms: one, the mind of the Finance Minister; two, the message that the Government wants to communicate; three, the method in which it seeks to implement it; four, the mechanism through which it will work its way and finally, the macro-economics that underlies the Budget estimates.

I would clearly state that there is a distinct sense of uncertainty in the mind of the Finance Minister about what is going to happen in the next three quarters. As such, it is a Budget for uncertain times, no doubt. Policy adventurism at this time could have been very dangerous. Therefore, the mindset is that of the 1970s: cautious and wary of the markets and the international environment. The message is clear of the 1990s: reforms are the only way forward.

In terms of the method, it is a Budget of uncertainty. There is no intent expressed on the banking and financial sector, especially insurance. Everything has been extended from the 2008-09 Budget. We have debt waiver, interest subvention to agriculture and to exports to 2010. Disinvestment has been deferred. The other method of the Budget is that it is an expenditure-oriented Budget with high incidence of revenue expenditure. In these times, the real issue is not the size of the fiscal deficit. In the current environment, the 6.2 per cent can perhaps be justified; it is the structure of the fiscal deficit that is the problem. The revenue deficit accounts for nearly 80 per cent of the fiscal deficit. Add to this the State's fiscal deficit of four per cent primarily incurred in revenue expenditure. This is the method of Budgetary management of the 1980s. So, 1970, 1990 and 1980 − that is the mindset of the Finance Minister today.

In terms of mechanics, the sectors identified are agriculture and infrastructure. But both have been binding constraints on growth. If India Infrastructure Finance Company Limited does work out modalities for refinancing 60 per cent of bank lending to Public-Private Partnership, infrastructure projects will definitely get a huge fillip. But doubt persists.

And lastly, the underlying macro-economics of the Budget is confusing. At one level, the current expenditure or consumption is seen as the driver of economic revival. But, on the other hand, this has been distributed and structured in such a way that it is bound to have an adverse impact on the savings rate in the economy.

Dr. C. Rangarajan, the former Governor of the Reserve Bank of India has recently stated that the roadmap to cut deficit could have been announced by the Finance Minister himself. Instead, it is being said by someone else, outside. I do not know why it was not mentioned in the Budget Speech by the Finance Minister himself.

The Government has proposed a borrowing programme of Rs. 4,00,000 crore in the current year to bridge the ballooning fiscal deficit of 6.8 per cent. But where is the money? How are you going to raise it? A fiscal deficit of 6.8 per cent of the GDP, which is up from 5.5 per cent postulated in February's Interim Budget, means an additional stimulus of nearly Rs. 80,000 crore. No Government, already saddled with a public debt overhand, can undertake such spending unless it feels compelled by circumstances. The Finance Minister, who believed that the worst of the economic slowdown is over, could have moderated spending. To not do that and to provide for a significant step up in spending implies a lack of faith in the revival of private demand. Where are we leading to? Has not the Government committed a serious error of judgement?

Sir, Budget making is supposed to be a simple exercise. That tells you how the Government will collect a certain amount of money and how it will spend it in the coming year. Unfortunately, now it has become an exercise in political one-upmanship. It is used to shower favours to selected interest groups and deny them to others. The 2009-10 Budget is being used to allocate Rs. 500 crore for 5 lakh Tamil refugees, almost all Sri Lankan nationals, in Sri Lanka while lakhs and lakhs of people of Orissa, Bihar and Assam lost everything because of flood during 2008-09 and have got nothing. Just how cynically these things are viewed is apparent from the utterances before the results were declared can be compared. The people of Orissa and Bihar may have voted for political parties that are not constituents of the UPA, but they remain citizens of this country. Are not they? The Prime Minister Dr. Manmohan Singh and his Union Government are as responsible for them as they are for the victims of the cyclone Aila. Funds provided after flood havoc in 2008 to Orissa is not being accounted for and the Government of Orissa is asked to return that amount. Is this the way how the UPA Government should take it out on the flood ravaged people of Orissa because they did not vote for them? Nobody is asking for doles, nor are we in need of gratis. We want our due. This Government has paid no heed whatsoever to our oft-repeated demands to grant a Special Category Status to Orissa.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): There is no need to mention the assistance provided to Sri Lankan Tamils. Thousands of people have been killed and lakhs and lakhs of people are suffering there. You can put forth your demand and pressurize the Government. But is it necessary to mention the assistance provided to Sri Lankan Tamils?

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): I have no quarrel with others. My only demand is, Orissa is a part of this country and we should be equally treated.

Recently I came across a statement of the Chief Minister of Karnataka. He is of the opinion that Iron ore should not be exported and it should be value added first. Orissa has been repeatedly saying this. The Chief Minister of Orissa Shri Naveen Patnaik has drawn the attention of the Prime Minister to this matter.

Especially, I would refer to the royalty structure which is in such a manner that the mineral rich States including Orissa are losing out substantially in resource generation for public investment. The mineral rich States do not get commensurate royalty for exploitation of several major minerals as the rates of royalty are not being raised in time.

The Central Statute on Minerals Development and Regulation provided for revision in royalty rates at an interval of three years which is supported by the recommendations of the Finance Commission. Besides, the Twelfth Finance Commission has also recommended that the rates of royalty should be revised on *ad valorem* basis. However, these provisions are not being followed. The delays in the revision of royalty on coal and other major minerals and inadequate revisions in royalties cause substantial loss of revenue to Orissa and other mineral rich States.

Why have we introduced a hybrid system since 1st August 2007? That does not compensate the mineral rich States in a fair manner. I would urge upon the Government to revisit the royalty structure on coal and other major minerals at an interval of every three years and determine the rate of royalty at the rate of 20 per cent ad valorem.

There is another interesting aspect. Further, tax levied by States on mineral bearing lands are also being adjusted against royalty. Such a practice unfairly constraints the constitutional powers of the State of levying tax on land including mineral bearing lands within its own jurisdiction.

Orissa has been broadly following a policy of encouraging value addition in the mineral sector. In order to ensure adequate supply of iron and other minerals to the mineral based industries that are investing in mineral rich States like Orissa, there is a need to cap exports of iron ore and other minerals at current levels. The people of the mineral rich States rightfully deserve to benefit from the

resource endowment.

The Finance Minister has profusely quoted Kautilya, but has led the country on the garden path of Charbak. The Government will rely heavily on borrowing in future to finance its various flagship schemes as the target for this has been increased to 34 paise of every rupee from 14 paise projected in the last Budget. It is said, "the borrowings is up by nearly 2.5 times." Now, Reserve Bank of India will auction Rs.15,000 crore worth of bonds this week, tomorrow to be specific, almost double the amount it was originally slated to borrow from the market this week. This is a signal. The Finance Minister is gambling on growth through borrow and spend formula which squarely rests on the shoulders of Reserve Bank of India.

In the Interim Budget, Sir, the Finance Minister had projected Rs.3.62 trillion market borrowings by the Government in the fiscal 2010 through RBI. At the time the fiscal deficit was estimated to be 5.5 per cent of India's Rs. 54.3 trillion GDP. Now, it has gone up to 6.8 per cent and there is no other way but to borrow an extra Rs.89,000 crore taking its overall borrowing programme in the year to Rs.4.51 trillion, a level which India has had never seen before.

My apprehension is that the situation will change in the second half of fiscal 2009. When many corporations, which have invested in banks, will plan to make fresh investment what will the banks do?

Indian public sector banks have sanctioned fresh loans worth Rs. 6.18 trillion. Banks will have no money to lend. So, interest rates will go up and money will become more expensive. Is the Finance Minister prepared to ride out from this situation? Through more spending and more borrowing as interest rate will rise, it will kill growth. Ultimately, what do you achieve Mr. Finance Minister?

I must say that this Budget does not have any major incentive or sweeping reforms but it indulges the UPA Government's core focus areas: productivity and food security. Funding for the new food scheme has not yet been accounted for in the Budget but it is likely to raise the food subsidy bill by Rs. 17,000 crore.

The Finance Minister has announced massive doles for agriculture. NREGA is up by 144 per cent, he said. But that is not agriculture; that is rural development. Allocation for NREGA is Rs. 39,000 crore. But for the critical Accelerated Irrigation Benefit Programme, it is just Rs 1,000 crore. This is where funds are spent to irrigate farm lands. Farm credit interest is lowered with a rider but farm allocation is very little compared to welfare schemes.

Earlier I had stated that this Government lacks seriousness in meeting its own stated objectives. I will cite three examples. Take for instance NREGA. Minimum wage is being increased from Rs. 80 to Rs. 100. A minimum of 100 days of employment to every rural household amounts to a greater amount. But the amount is Rs. 39,100 crore and this is an increase of only Rs. 2350 crore over the amount spent last year.

Similarly, on food security, food subsidy in the Budget is only Rs. 8862 crore, more than what was spent last year. Most of this already accounted for by the increase in Minimum Support Price for the Rabi harvest. Additional funds will clearly be necessary to make such a law effective.

On education the Budget allocations are truly surprising. The Right to Education Bill is there in this Parliament. This, when made into law, will require significant financial inputs from the Government. But the increase in spending on elementary education is less than Rs. 200 crore which suggests a complete lack of seriousness about implementation.

One thing is clear. If the Government really wants to do what it has promised to the people, it will have to spend more. But that is very difficult because it has tied its own hands.

Before concluding, I am eager to share a thought about NREGS. It is a colossal failure though it has been touted as a grand success by this Government. The Scheme was a golden opportunity for the Government to revive village economies, build rural infrastructure, and empower rural poor. But a few months ago, the Comptroller and Auditor General has noted the dismal performance of NREGS. The report states that barely 3.2 per cent of the registered households have benefited from the Scheme. The C&AG's rebuke has fallen on deaf ears. Without plugging the loopholes, why are you going ahead with this programme? It would be wrong to expect the Budget to provide instant answers to our inherent problems like poverty, deprivation and hunger. But the manner in which the Government has spelt out its programmes in this Budget, is not at all encouraging. To me, it is without focus and falls in between the socialist populism and capitalist jargons. Either you follow Chanakya or you follow Charbak. Both were great thinkers of this land. But quoting Chanakya and going along Charbak way will not help the people nor this Government.

**श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़):** सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। वैसे 2009-2010 का जो बजट है, इस बजट से पूर्व जब लोक सभा के चुनाव हुए, तब यूपीए की ओर से और खास तौर से कांग्रेस की ओर से सारे देश में आम आदमी की काफी चर्चा हुई। आम आदमी की सुरक्षा के लिए, आम आदमी के हितों के लिए सरकार द्वारा अपील की गई और चुनाव के बाद यह पहला बजट है। दुर्भाग्य से मुझे यह कहना

पड़ रहा है कि इस बजट में आम आदमी कहीं भी दिखाई नहीं देता है, बल्कि यह आम आदमी विरोधी बजट है। इसलिए पूरे देश में इस बजट के बारे में जो चर्चा है, वह काफी निराशाजनक है। समाज का हर स्तर इस बजट से निराश है। इसलिए यह बजट आम आदमी विरोधी बजट है। मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ बातें रखना चाहूँगा। जैसे किसानों की आत्महत्या को लेकर 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, लेकिन इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कल हमारे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री दिल्ली आए हुए थे। दिल्ली के सांसदों के साथ कल एनैक्सी में बैठक हुई जहाँ पर किसानों की आत्महत्या पर चर्चा हुई। दत्ता मेघे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे मेरी बात से सहमत होंगे। जैसे 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज किसानों को कर्ज़ा माफी के लिए सरकार द्वारा किया गया, उससे पूर्व जहाँ से यह आत्महत्या का सिलसिला शुरू हुआ और दुर्भाग्य से सारे देश में जितने किसानों ने आत्महत्या की है, उसमें सर्वाधिक आत्महत्याएँ महाराष्ट्र में हुई और महाराष्ट्र में सर्वाधिक आत्महत्याएँ विदर्भ में हुई। जब इन आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ने लगा, तब हम प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी से मिले थे - शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के सारे महाराष्ट्र के सांसद और हमने उनको कहा था कि आप विदर्भ का दौरा करिये। उन्होंने इस बात को कुबूल किया। वे नागपुर आए, विदर्भ में आए और आने से पूर्व उन्होंने विदर्भ के कुछ जिलों के लिए पैकेज डिक्लेयर किया था। कल जब इस बात पर चर्चा हुई, तब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि जो पैकेज प्रधान मंत्री जी ने विदर्भ के लिए घोषित किया है, उससे किसानों की आत्महत्याएँ अब तक रुकी नहीं हैं। आत्महत्याओं का सिलसिला अब भी चल रहा है। इस पैकेज में और धनराशि भारत सरकार की ओर से मिलने की आवश्यकता है। राज्य के मुख्य मंत्री ने कल सांसदों से मिलते हुए कहा कि वे स्वयं भी प्रधान मंत्री जी से इस संदर्भ में मिलने वाले हैं। सभापति महोदय, यह हालत आत्महत्या करने वाले किसानों की है। आपने पैकेज तो डिक्लेयर किया है। जब इसके बाद सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स के लिए बहस आई थी, तब उस समय के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने केवल 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान उस सप्लीमैंट्री बजट में किया था जिसको इस सदन ने पारित किया था। उसके बाद एक रुपये का भी प्रावधान बजट में अब तक नहीं किया गया है। ऋण माफी के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है। सरकार कहती है कि किसानों के प्रति हमारी सरकार के मन में...।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please take your seat.

Now, it is 6 p.m. I have a long list of speakers. Therefore, if the House agrees, we can extend the time of the House till 8 p.m. Is it all right?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Okay, the time of the House is extended till 8 p.m.

Shri Anant Gangaram Geete, you can continue your speech now.

**18.00 hrs.**

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please sit down. Shri Geete is on his legs.

...(*Interruptions*)

**श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन):** महोदय, दोपहर में कहा गया था कि शून्यकाल के लिए समय दिया जाएगा...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The House would sit up to 8 o' clock today. You would definitely get a chance.

...(*Interruptions*)

**श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर):** महोदय, आप पहले शून्यकाल ले लीजिए, उसके बाद बजट पर चर्चा जारी रखिए...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You will get your chance, do not worry. Please sit down, now.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Geete, you may please continue.

...(*Interruptions*)

**श्री घनश्याम अनुरागी :** महोदय, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। हम भी किसानों की बात उठाना चाहते है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The time of the House has been extended up to 8 o' clock. Therefore, you would get a chance to raise your issue at 8.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, after end of the ongoing business, we would take up the other issue, that is, *'Zero Hour'.*

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please listen to me. In the morning, the hon. Speaker said that at the end of the debate today, we would take up the *Zero Hour.* First five Members in the list were given chance to speak under 'Zero Hour' at 12 o' clock today. The remaining Members in the list, would be given chance to raise their matters at the end of the debate today. At 8 o' clock, you would get chance to raise your matters.

Now, please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We are going to give the opportunity to all the Members in the list. At 8 o' clock, we are going to take up the *Zero Hour.*

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Geete, you please continue.

...(*Interruptions*)

**श्री लालू प्रसाद (सारण):** महोदय, आपने आठ बजे तक का समय बढ़ा दिया है, यह अच्छी बात है। लेकिन क्या कल चर्चा नहीं होगी? क्या कल जवाब दिया जाएगा?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Laluji, you are an experienced man. You know the procedure. At the end of the business only we would take up the *Zero Hour* and not in the middle of the debate.

When the House has given consent to extend the time of the House up to 8 o' clock, there is no point in raising the issue that you would insist for taking up the *Zero Hour* at 6 o' clock.

SHRI LALU PRASAD : Would the discussion end today or not?...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, I would suggest a way out. हम दोनों के बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। सात बजे तक हम बजट पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद ज़ीरो ओवर ले लेते हैं। But then, my request to the hon. Members would be that they should not insist for taking longer time for the discussion on the General Budget.

MR. CHAIRMAN: If you accept it, we would have the discussion on the General Budget up to 7 o' clock and then after that, we would take up the *Zero Hour.*

So, instead of having a discussion up to 8 o' clock, the discussion would be over by 7 o' clock and then we would take up the *Zero Hour.*

Is it okay?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: All right.

Mr. Geete, please continue.

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** महोदय, सरकार हमेंशा किसानों की बात करती है और वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि किसानों को काफी सुविधाएं हमने दी हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की गई है, उनके लिए इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए एक और घोषणा की है कि वन टाइम सैटलमेंट के पीरीयड को तीस जून से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2009 तक कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि वन टाइम सैटलमेंट प्रपोज़ल को कोई किसान स्वीकार करेगा। कुछ किसान हैं, जिनका आपने सौ प्रतिशत ऋण माफ किया है, जबकि कुछ किसानों को आप कह रहे हैं कि आप 75 प्रतिशत दीजिए 25 प्रतिशत हम छूट देंगे। कुछ किसान ऐसे भी हैं, जिनको आप कोई राहत नहीं दे रहे हैं। जिनको आप कोई राहत नहीं दे रहे हैं, उनके लिए वित्त मंत्री जी ने एक घोषणा और की है कि जो किसान ऋण का रैगूलर पैमेन्ट करते हैं, उनके ऋण पर जो सात प्रतिशत का ब्याज लगता है, उस पर एक प्रतिशत का डिसकाउन्ट दिया जाएगा।

**18.05 hrs**.

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

एक करोड़ पर देश के किसानों को अलग-अलग हिस्सों में बांट कर, एक्चुल जो किसान है, जो किसान छोटा, मेहनत करने वाला या मध्यम है और जो अनाज या धान की खेती करता है, उस किसान के साथ इस प्रकार से भेदभाव करना और वह भी सरकार की ओर से, यह सीधे-सीधे किसानों के साथ नाइंसाफी एवं सरासर धोखा है। एक परसैंट डिसकाउंट की बात की है, यह कोई किसानों के लिए खुशी की बात नहीं है।

सभापति महोदय, इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। आज महंगाई दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्री जी की पूरी बजट स्पीच में महंगाई का जिक्र तक नहीं है। उन्होंने इस बात को स्वीकार तक नहीं किया कि देश में महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी उससे परेशान है। आम आदमी का महंगाई की मार से जीना मुश्किल हो चुका है। उसका जिक्र तक वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में नहीं किया है।

सभापति महोदय, कल मेरी बीबी मुझे बता रही थी कि मुंबई में जो अरहर की दाल है, हम लोग उसे तुअर की दाल कहते हैं, उत्तर में अरहर की दाल कहते हैं, आज उस दाल का रेट 85 रुपए किलो है। दिल्ली में कल एक सांसद अरहर की दाल खरीद कर लाए हैं, वे मुझे जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में इस दाल का रेट 85 रुपए किलो है। चावल का रेट भी 40 रुपए से कम नहीं है, अच्छा गेहूं भी 30 रुपए से कम नहीं है। आज किसी भी प्रकार की दाल का रेट बाजार में 60 रुपए से कम नहीं है। तिलहन और तेल की बात अलग है। इन सब चीजों के दाम दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इस साल बजट में महंगाई की चर्चा तक नहीं हुई है। उसे रोकने का कोई प्रयास वित्त मंत्री जी ने नहीं किया है। आम आदमी महंगाई से परेशान है, उस आम आदमी के बारे में महंगाई को रोकने के लिए इस बजट में कोई प्रयास नहीं है।

सभापति महोदय, नरेगा की काफी चर्चा की जाती है। हमारे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह इस विषय में काफी खुश रहते हैं। उनकी जो मंशा है, उनका जो संकल्प था, वह बिलकुल अच्छा था, उसमें मुझे कोई आशंका एवं आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। पूरे देश में नरेगा फ्लॉप स्कीम है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सौ प्रतिशत फ्लॉप है। नरेगा को लेकर सरकार जिस तरह से अपनी पीठ थपथपाती है - जैसे देश की सारी बेरोजगारी खत्म हो गई। नरेगा टोटली फ्लॉप स्कीम है। नरेगा से बेरोजगारी में कोई कमी नहीं हुई है। आज पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि इस रिसेशन का हमारे देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस आर्थिक मंदी का हमारे देश पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन आज इस मंदी से हमारा उद्योग जगत प्रभावित है और उद्योग जगत प्रभावित होने के कारण बेरोजगारी बढ़ने की आशंकाएं बढ़ी हैं।

सभापति महोदय, मैं यहां एक उदाहरण दूंगा। हमारा सिविल एविएशन मंत्रालय है। इस समय यहां प्रफुल पटेल जी उपस्थित नहीं हैं। पिछले महीने हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को यह फैसला करना पड़ा, सीएमडी को घोषणा करनी पड़ी कि अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव हैं, वे एक महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे, छोड़ देंगे।

सभापति महोदय, जब तक एग्जीक्यूटिव की बात थी, तब तक तो हम समझ सकते थे, लेकिन हमारे एयर इंडिया के कर्मचारियों को आज तक सैलरी यानी वेतन नहीं मिला है। 15 तारीख तक एयर इंडिया के कर्मचारियों को वेतन मिलने की संभावना नहीं है और 15 तारीख के बाद भी इस महीने का या पिछले महीने का वेतन मिलेगा या नहीं, यह आशंका आज एयर इंडिया के कर्मचारियों के मन में है, जिसकी वजह से वे परेशान हैं। एयर इंडिया के लाखों कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें आज तक पिछले महीने का वेतन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नहीं दे पाई है। इसलिए यह कहना कि मंदी का हम पर कोई असर नहीं है, ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, आज देश भर में करोड़ों शिक्षित बेरोजगार हैं। मेरे पास पूरे देश के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उस महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 42 लाख है। अकेले महाराष्ट्र में 42 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। आज मंदी के कारण दिन-ब-दिन हमारी इंडस्ट्रीज बन्द होती जा रही हैं। इसका भी बेरोजगारी पर प्रभाव हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी की चर्चा इस बजट में कहीं भी नहीं की गई है। मंदी से लड़ने के लिए इस बजट में कोई प्रॉवीजन नहीं किया गया है। बेरोजगारी को हटाने का कोई प्रॉवीजन नहीं है। आज अगर बेरोजगारी से कोई व्यक्ति परेशान है, तो वह आम आदमी है, लेकिन उस आम आदमी की बेरजोगारी की चर्चा भी इस बजट में बिलकुल नहीं है, उसे रोजगार देने की कोई चर्चा नहीं है।

सभापति महोदय, अनेक माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी ने भी क्रेडिट लेने के लिए यहां कहा कि हमने मुम्बई के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रॉवीजन किया है। यह किस लिए किया है। इस प्रोजैक्ट का नाम बृमस्टैड (BRIMSTAD) प्रोजैक्ट है। उन्होंने जो घोषणा की है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन यह प्रोजैक्ट वर्ष 2005 का है, जिसके लिए इस बार बजट में घोषणा की गई है। इसकी घोषणा प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह ने वर्ष 2005 में मुम्बई में जाकर की थी। जब मुम्बई में भारी वर्षा हुई, जब मुम्बई में तबाही मची, सारी मुम्बई डूब गई, तब इस बृमस्टैड प्रोजैक्ट के लिए 1200 करोड़ की घोषणा वर्ष 2005 में डॉ. मनमोहन सिंह ने की थी। उसके लिए आपने अब वर्ष 2009 में 500 करोड़ रुपए का प्रॉवीजन किया है।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऐसा यह पहला बजट है, जो मैं सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की। मैं भी इसे अच्छा समझता हूं, लेकिन इसमें जो रैवेन्यू कलैक्शन है, वह 6 लाख करोड़ रुपए का है, उसमें 28 प्रतिशत राजस्व अकेले महाराष्ट्र राज्य से आता है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): You should be proud of it. ...(*Interruptions*)

**श्री अनन्त गंगाराम गीते :** जी बिलकुल। श्री नारायणसामी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो आपको 6 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिलने वाला है, जिसके आपने आंकड़े दिए हैं, उसमें से अकेले महाराष्ट्र से आपको 28 प्रतिशत राजस्व मिलने वाला है और महाराष्ट्र में भी सबसे अधिक मुम्बई से मिलने वाला है। इस प्रकार यदि आप देखें, तो सर्वाधिक राजस्व आपको मुम्बई से आता है।

MR. CHAIRMAN : Shri Geete, now you can conclude. Please take your seat.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय, उड़ीसा के हमारे एक साथी, श्री महतो जी ने आज यहां कहा कि उड़ीसा को पूरी तरह से बजट में नैग्लैक्ट किया गया है। उसी प्रकार से मैं भी कहना चाहता हूं कि इस बजट में महाराष्ट्र और मुम्बई को पूरी तरह नैग्लैक्ट किया गया है। दुर्भाग्य से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जिस प्रदेश से इस देश को लगभग वन-थर्ड रैवेन्यू मिल रहा है, उस महाराष्ट्र को भी इस बजट में पूरी तरह से नैग्लैक्ट किया गया है और उसकी ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, आज हालत यह है कि पूरे देश में सूखे की स्थिति है। पिछले कई दिनों से मुम्बई, कोंकण और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अच्छी वर्षा हो रही है, लेकिन सारे महाराष्ट्र और पूरे देश में अच्छी वर्षा नहीं हो रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि देश सूखे की चपेट में है।

आज मुम्बई में आबादी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। मुम्बई की आबादी का जो ऑफिशियल आंकड़ा है, वह 1.40 करोड़ है, लेकिन जो अनऑफिशियल आबादी वहां पर है, अगर उसको देखा जाये तो लगभग दो करोड़ की आबादी आज मुम्बई की हो गई है। आज मुम्बई में भी पानी की किल्लत है। आज 30 परसेंट कट मुम्बई शहर में पानी का हो चुका है और यह भय आज मुम्बई के कारपोरेशन को है कि यदि भविष्य में वर्षा नहीं होती है तो दुर्भाग्य से मुम्बई के लोगों को कुंए का पानी पीना पड़ेगा, मुम्बई को बोरवैल का पानी पीना पड़ेगा, मुम्बई को समुद्र का पानी पीना पड़ेगा, यह स्थिति आज मुम्बई की है।..(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Anant Geete, thank you. No, it is okay. Please take your seat.

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** मैं खत्म कर रहा हूं। यह मेरा लास्ट सेंटेंस है, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि मुम्बई शहर को बचाने के लिए, मुम्बई की पानी की समस्या को हल करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज वाटर प्रोजैक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपये मुम्बई के लिए भारत सरकार को देने चाहिए, प्रधानमंत्री को देने चाहिए।

महाराष्ट्र को जो एलोकेशन आप स्टेटवाइज़ करते हैं, उसमें निश्चित रूप में एक तिहाई हिस्सा यदि रेवेन्यू में महाराष्ट्र का है तो एक तिहाई एलोकेशन की मांग नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप में महाराष्ट्र के एलोकेशन में बढ़ोत्तरी सरकार को करनी चाहिए। यह मांग करते हुए यह बजट चूंकि आम आदमी का विरोधी है, इसलिए मैं बजट का समर्थन नहीं कर सकता।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Shri Geete.

Before I call upon the next speaker, please understand that you have to confine to the time allotted to you. Shri Anant Geete has taken eight minutes more. Shri Geete, since you were making good points, I did not want to interrupt you.

Now Shri Hukmadeo Narayan Yadav is to speak. Shri Yadav, how much time are you going to take? There are many speakers from your party.

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** सभापति जी, हम ज्यादा बैठेंगे। आज हम आठ बजे तक बैठे हैं, कल 10 बजे तक बैठेंगे।

**सभापति महोदय :** हुक्मदेव जी, आप कितना टाइम लेंगे?

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):** आप जहां पर उचित समझेंगे, मुझे एक दो बार हिदायत करेंगे तो मैं अपनी गाड़ी की चैन खींच लूंगा। वैसे जब मैं बोलता हूं तो एक्सप्रैस में चलता हूं, जिसमें कोई ब्रेक नहीं रहता है, लेकिन मैं आपके आदेश को मानूंगा, फिर आप 10 मिनट दें या 12 मिनट दें। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Your party's time is there. You can take time according to the number of speakers from your party.

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** सभापति महोदय, मैं गांव का किसान होने के कारण और एक गौपालक वंश का होने के कारण अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले, चूंकि मैं किसान हूं, इसलिए इस देश की धरती माता, गऊ माता और गंगा माता को नमस्कार करता हूं।

इस सरकार में बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी जी का मैं सम्मान करता हूं, वे विद्वान हैं, योग्य हैं, अनुभवी हैं, कर्मठ हैं, तर्क में अच्छे निपुण हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस बजट के एक-एक अंश का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि इस बजट में न दिशा है, न दृष्टि है और न संकल्प है। जब दिशा नहीं हो, दृष्टि नहीं हो और संकल्प नहीं हो तो फिर वह किसी रास्ते की ओर नहीं जा सकता है। मैं इसलिए इस बजट का विरोध करता हूं कि मैं गांव का किसान हूं और इस बजट में हमारे किसानों को जो उचित हिस्सा मिलना चाहिए था, वह जनसंख्या के आधार पर हमें उचित हिस्सा नहीं मिला है।

जब हम इस देश के अन्दर सरकारी आंकड़े को निकाल कर देखते हैं तो हमारे किसानों की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर हमको कितना आपने इस बजट में हिस्सा दिया है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप हमको जनसंख्या के आधार पर हिस्सा देते हैं। दूसरे लगातार किसान मजदूर बनते गये हैं। जहां 1951 में कृषि पर 49.9 प्रतिशत लोग निर्भर थे, वहां 1991 में कृषि पर निर्भर लोग 35.2 प्रतिशत बच गये। इतने किसान कहां चले गये? वे खेतिहर मजदूर बन गये। जिस सरकार ने, जिस व्यवस्था ने किसानों को मजबूर बनाया है, भूमिहीन बनाया है, किसानों को कृषि मजदूर बनाने के लिए व्यवस्था पैदा की है, उस बजट का कैसे समर्थन किया जा सकता है, उस व्यवस्था का हम कैसे समर्थन कर सकते हैं। आपने केवल उसकी जमीन का किसान को हिस्सा नहीं दिया, बल्कि भारत के किसान का आधार, भारत की कृषि का आधार गौवंश है। लगातार इस देश में गौवंश का ह्रास हुआ है। अगर

आप भारत सरकार के इस आंकड़े को निकालकर देखेंगे तो जहां इस देश में एक हजार आदमी पर गौधन की संख्या 1951 में 430 थी, वहां वही संख्या 1992 में आकर केवल 242 बचती है। इसका मतलब निरंतर गोधन का ह्रास हुआ है। हमारे देश के अंदर एक समय एक हजार पर कुल पशु 810 होते थे, जो वर्ष 1991 आते-आते घटकर 555 हो गये। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 31.5 प्रतिशत पशुधन का ह्रास हुआ है। जिस देश में पशुधन का ह्रास हो, किसानों को उचित हिस्सा न मिले, क्या उस बजट को उचित कहा जा सकता है? यह किसान विरोधी, गांव विरोधी और पशुधन पालने वाले, पिछड़े, दलित, वनवासी, जो पशुधन पालते हैं, गाय, मुर्गी, भेड़, भैंस, गधा, खच्चर, ऊंट पालते हैं और उससे अपना जीवन चलाते हैं, उनकी जीविका का आधार, आर्थिक आधार छीना जा रहा है। यह कभी समर्थन करने योग्य नहीं है।

महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारी जमीन भी कम होती चली गयी है। जहां वर्ष 1950-51 में हम जमीन जोतते थे, तब किसान की कृषि का हिस्सा 50 प्रतिशत था, जो आज निरंतर घटते-घटते 20 के नीचे तक चला गया है। जब हम कृषि से राष्ट्रीय आय में इतना योगदान देते थे, तो यह क्यों घट गया है? यह इसलिए क्योंकि हमारी आमदनी में कमी है, क्रयशक्ति में कमी है। हमारे साथी बोलते हैं, धान, चावल, गेहूं, दाल, तिल ओर सरसों की कीमतें बढ़ती हैं, तो देश में हाहाकार मचता है। मैं किसान होने के नाते कहता हूं कि जब सीमेंट के दाम बढ़ते हैं, लोहे के दाम बढ़ते हैं, कपड़े के दाम बढ़ते है, खाद के दाम बढ़ते हैं, औद्योगिक उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं, तो इस देश में हाहाकार क्यों नहीं मचता है?

महोदय, मैं अन्न पैदा करता हूं। एक तरफ मैं विक्रेता हूं, तो दूसरी तरफ मैं खरीददार भी हूं। मैं अपने कृषि उत्पादन को बाजार में बेचता हूं, उससे औद्योगिक माल खरीदता हूं। यूरिया जहां वर्ष 1967 में 45 रूपए बोरी मिलती थी, जब मैं पहली बार असेंबली में एमएलए बनकर आया था, लेकिन आज यूरिया का रेट कहां पहुंच गया है? यूरिया की कीमत 300 रूपए तक चली गयी। मैं मांग करता हूं कि एक आधार-वर्ष बनाया जाए, चाहे वर्ष 1967 को मानो, 1977 को मानो, 1960 या 1970 को मानो, लेकिन एक आधार-रेखा खींचिए कि उस समय कृषि उत्पाद, धान, चावल, गेहूं, दाल की कीमत क्या थी और औद्योगिक उत्पाद की क्या कीमत थी? हमारे खेतिहर सामान की कीमत कछुए की चाल से बढ़ती हैं, जबकि औद्योगिक उत्पाद की कीमत घोड़े की चाल से बढ़ती है। हमारा किसान लुटता जा रहा है, वह आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसे कृषि उत्पाद की सही कीमत नहीं मिलती है।

महोदय, मेरी मांग है कि एक कृषि मूल्य निर्धारण आयोग बनाया जाए। उसमें कृषि उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद दोनों की लागत निकालकर कीमत तय की जाए। हमारे यहां खेती में पैदा होने वाले अनाज की कीमत किसान आयोग तय कर देता है। हमारे उत्पाद की कीमत सरकार तय करे, लेकिन सीमेंट की कीमत सरकार नहीं तय करेगी, क्योंकि उद्योग के जरिए से पैसा है, लक्ष्मी है, वहां से चुनाव में फंड आता है, जिसका खाते हैं, उसका गाते हैं, पैसा औद्योगिक घराने से लेते हैं, इसलिए बजट उनके हिस्से में बनाते हैं। हम इनको पैसा कहां से देंगे? हम तो अपनी हड्डी गलाते हैं। दधीचि के जैसे धूप में, ताप में, शीत में जलते हैं, ठिठुरते हैं, मरते हैं, बिना कपड़ा के रहते हैं। अंधेरी रात में अपने कुएं पर रहकर, अपने खेत में रहकर खेत को सींचते हैं। हमें न सांप का डर है, न बिच्छू का डर है और न जानवर का डर है। हम इतनी हिम्मत के साथ राष्ट्र के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं, लेकिन हम फिर भी उपेक्षित हैं। इसलिए कि हम पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं।

महोदय, सरकार का जैसा चरित्र होगा, वैसा ही बनेगा। इस सरकार का चरित्र क्या है? मंत्रिमंडल को देखा जाए, तो क्या इसमें कोई यादव, जाट, गुर्जर, कुर्मी, कुशवाहा, दलित या पिछड़ा है, जो एक नंबर की पंक्ति पर बैठा हो? जहां न किसान होगा, न मजदूर होगा, न गांव वाले सरकार में होंगे, उस सरकार से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि वह हमारी बात को सुनेगी? आज किसान इतनी बड़ी संख्या में हैं, क्या इनके मंत्रिमंडल में कोई किसान है? इस सदन में पहली पंक्ति पर नजर डालें, आगे की पंक्ति पर कोई किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, पिछड़े या दलित का बेटा बैठता है क्या? जब सदन में पहली पंक्ति में हम नहीं हैं, दूसरी पंक्ति में हम नहीं हैं, तो हमारी बात सुनने वाला कौन है? बजट कौन बनाता है? अगर आप उसे मंत्री बनाते हैं, तो मंत्री में क्या दे देते हैं, श्रीमान? राज्यमंत्री का पद दे देते हैं अर्थात बड़े मंत्री के पीछे एक साहबल्ला देते हैं, जैसे दूल्हा शादी करता है, साहबल्ला गाली सुनता है। वैसे मंत्रिमंडल में बड़े-बड़े बाबू कैबिनेट मंत्री बनेंगे, पिछड़े, दलित और आदिवासी को ये उनके राज्यमंत्री बना देंगे कि आप उनका बस्ता ढोइए, उनके आफिस में बैठिए, इनकी टेबल पर बैठिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सरकार बने, आप उसमें बने रहो। कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रणव मुखर्जी जैसे विद्वान, तेजस्वी, चरित्रवान, दमदार, बंगाल की वीरभूमि से आए हुए, इनको कभी एक नंबर की कुर्सी नहीं मिली।

बाबू जगजीवन राम जैसे व्यक्ति ने अपना जीवन गंवा दिया लेकिन मरने के बाद भी उनकी लाश को गांव में जाकर जलवाया गया, क्योंकि यदि जगजीवन राम जी की लाश दिल्ली में रहेगी तो हिन्दुस्तान के करोड़ों दलित उनसे प्रेरणा पाएंगे। जगजीवन राम जैसे व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया गया। जिन्होंने बाबू जगजीवन राम जैसे व्यक्ति को इज्जत नहीं दी, उस पार्टी से हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वह किसी दलित को इज्जत दे। कहने के लिए भले ही कह दें कि हम दलित की बेटी को स्पीकर बना रहे हैं। हम उस कुर्सी पर बिठा रहे हैं। धिक्कार है। जब कहा जाता है कि एक दलित की बेटी को कुर्सी पर बिठा रहे हैं, एक आदिवासी को कुर्सी पर बिठा रहे हैं, एक पिछड़े को कुर्सी पर बिठा रहे हैं, मेरे स्वाभिमान को, मेरे सम्मान को आप धिक्कारते हैं, इसलिए कि मैं भिखमंगा हूं क्या। कोई दलित व्यक्ति भिखमंगा है क्या? कोई पिछड़ा व्यक्ति भिखमंगा है क्या? आप देने वाले कौन हैं जो कहते हैं कि हमने दिया। आप कौन होते हैं देने वाले? यह मेरा अधिकार है। आज नहीं देंगे तो हम लड़कर ले लेंगे। हम नहीं लेंगे तो हमारी संतान ले लेगी। अगर नहीं भी लेगी तो देश में भूचाल आएगा, न यह संसद रहेगी, न यह सरकार रहेगी, न यह माटी की कहानी रहेगी। इसलिए याद कीजिए कि आपकी सरकार का जैसा वर्ग चरित्र है, महान् क्रान्तिकारी नेता लेनिन ने कहा था, आप जैसा समाज बनाना चाहते हैं, अपनी पार्टी के स्वरूप को वैसा खड़ा कीजिए। आपकी पार्टी का क्लास, करैक्टर क्या है? आपकी पार्टी का वर्ग स्वार्थ क्या है? जो आपका क्लास, करैक्टर है, जो आपका इंटरस्ट है, उसके हिसाब से बजट जरूर बनाते हैं, बाकी हमें क्या देते हैं।...(व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जमीन कितनी थी जिसे हम जोतते थे। 1984 में 13.11 करोड़ हैक्टेयर जमीन पर खेती होती थी। वह घटते-घटते आज केवल

12 करोड़ से भी नीचे चली आई है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारी खेती की उपजाऊ जमीन लेते हैं। उसमें उद्योग बनाओ, उसमें सड़क बनाओ, उसमें कारखाने लगवाओ। बंजर भूमि में क्यों नहीं जाते? छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, जहां जमीन बंजर है, जहां परती जमीन है, जहां ऊसर जमीन है, जहां ऊबड़-खाबड़ जमीन है, उन्हें समतल कीजिए, वहां कारखाने लगाइए। बंजर को आबाद कीजिए, बंजर में कारखाने लगाइए। जब कारखाना लगेगा तो वहां सड़कें जाएंगी, बिजली जाएगी, पीने का पानी जाएगा, वहां मकान बनेंगे, वहां अधिकारी रुकेंगे, फिर वहां बाजार बसेगा। जब बाजार बसेगा तो गांव के गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित दुकान खोलेंगे। आपकी नीयत खराब है। आप चाहते हैं कि उन पिछड़े इलाकों में कारखाने न लगें जिससे शोषित, दलित, पिछड़े लोग रोजगार करें, पान बेचें, चाय बेचें, सब्जी बेचें, कपड़ा बेचें, खोमचे में सामान बेचे और अपने परिवार का गुजारा चलाएं। इसलिए आपसे अगर कोई उम्मीद करता है तो यह उसका धोखा है। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारी जमीन कृषि योग्य है। हरियाणा, पंजाब में जमीन लेते हैं तो 20 लाख रुपये, 30 लाख रुपये का मुआवजा देते हैं, लेकिन बिहार में एक लाख रुपये, दो लाख रुपये, तीन लाख रुपये, चार लाख रुपये का मुआवजा देते हैं। हमारी जमीन यहां से ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन हमें मुआवजा कम मिलता है। हरियाणा में 30 लाख रुपये, बिहार में 5 लाख रुपये, एनएचआई की सड़क बनती है, बिहार सरकार द्वारा जो नोटीफिकेशन निकलता है, वह भी आप पूरा नहीं कर पाते। मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की हालत खराब है। अगर आप इसके कारण जानेंगे तो देखेंगे कि कृषि में मजदूर कम हैं। मार्जिनल किसानों की संख्या के आधार पर वहां के लोगों के जीवन चलते हैं। बिहार में लघु किसानों की संख्या ज्यादा है, हरियाणा, पंजाब में सीमान्त किसान, लघु किसान की संख्या के साथ-साथ खेतीहर मजदूरों की संख्या भी कम है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यह जो असंतुलन है, विषमता है, इसे रोकें और संतुलन लाएं। मैंने इसीलिए कहा कि न आपकी दृष्टि है, न आपकी दिशा है, न आपका संकल्प है। हंमारी दिशा क्या होनी चाहिए - स्वाभिमानी, स्वावलम्बी, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण। दृष्टि तात्कालिक, दीर्घकालिक और प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिए। हमारा संकल्प होना चाहिए समय सीमा के अंदर, समग्रता में लक्ष्य को प्राप्त करना। जब हम कृषि को प्राथमिकता, ग्रामीण उद्योग को दूसरे नम्बर पर, वृहद उद्योग को तीसरे नम्बर पर रखेंगे, गांधी जी ने सपना देखा था, यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद किसान नेता आए, पटेल चले गए, आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह आए, इस देश ने चौधरी चरण सिंह को नहीं माना। आजादी के बाद जो भी नेता आए, डा. लोहिया आए, पिछड़े, दलित को जगाने आए, अस्पताल में जाकर उन्हें मार दिया गया, ऑपरेशन के जरिए मारा गया।

हिन्दुस्तान के सांस्कृतिक राष्ट्र को चेतना देने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय की लाश ...(व्यवधान) उनकी हत्या करके लाश को ट्रेन में फेंक दिया गया। ...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार या कांग्रेस पार्टी की एक ही बात रही है कि जो शीश उठायेगा, उसकी गर्दन काट देंगे। जो गुलाम बनकर आयेगा, वह उनके साथ रह जायेगा। ...(व्यवधान) ये कभी शेर को साथ नहीं रहने देते। ...(व्यवधान)

ये गुलामों को पूछते हैं। ...(व्यवधान) ये गुलामों को साथ रखते हैं। जो शेर बनकर आयेगा, वह जरा गर्दन उठा दें ...(व्यवधान) क्या कभी किसी की गर्दन बची है? ...(व्यवधान) इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। ...(व्यवधान) मैं बिहार से आया हूं। लालू प्रसाद जी यहां मंत्रिमंडल में थे। वे सदन में बैठे हुए हैं। वे आज भी हमारे साथी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। आप बिहार के साथ अन्याय क्यों करेंगे? अगर आप बिहार के साथ अन्याय करेंगे, तो बिहार ने भी चुनाव में बदला चुकाया है। आप एक बात याद रखो कि अगर यह अन्याय जारी रहेगा, तो उस बिहार से ऐसी अग्नि निकलेगी कि कांग्रेस पार्टी का वंश नाश कर देंगे, लेकिन बिहार के लोग छोड़ेंगे नहीं। ...(व्यवधान) इसलिए आप हमारा हिस्सा दे दो। ...(व्यवधान) हम कोसी में डूबते हैं। ...(व्यवधान) बाढ़ में मरते हैं। ...(व्यवधान) मैं कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूं।...(व्यवधान) मैं किसी नेता को न कहकर कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूं। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** हुक्म देव जी, क्या आपको बजट के बारे में कुछ बोलना है?

â€¦(व्यवधान)

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** सभापति महोदय, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) जहां वर्ग चरित्र जैसा होगा, वर्ग स्वार्थ जैसा होगा, वर्ग हित जैसा होगा, लेनिन के शब्दों में कि आप जैसे समाज की रचना चाहते हैं वैसे ही पार्टी का चेहरा प्रस्तुत करो। इसलिए मैं आपसे इस बारे में प्रार्थना करता हूं। प्रणब बाबू, सदन में आ गये हैं। जब मैं राज्य सभा में था तब ये लीडर थे। मैं उनका सम्मान करता रहा हूं। ये भी हम लोगों को असलियत बताते रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र, योग्यता, दक्षता, विद्वता और अनुभव में प्रणब बाबू जैसे आदमी को जो पार्टी उचित सम्मान नहीं दे सकती, वह पार्टी दुनिया को क्या सम्मान देगी? वह पार्टी किसानों को क्या सम्मान देगी, पिछड़ों को क्या सम्मानित करेगी, वह दलितों को क्या सम्मानित करेगी?

इसलिए मैं आपसे अंत में केवल एक ही बात कहूंगा कि इस बजट में ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या प्रणब बाबू प्रधान मंत्री होते? ...(व्यवधान)

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** अगर प्रणब बाबू प्रधान मंत्री होते, तो मैं इनके बजट का विरोध नहीं करता, क्योंकि ये वित्त मंत्री हैं। इन्होंने बजट पेश किया है, लेकिन दिशा किसी और की है, दृष्टि किसी और की है, नाच कहीं और होता है और कठपुतली को नचाता कोई और है। हम उस अदृश्य शक्ति का विरोध करते हैं, जिसने अपनी दृष्टि, अपनी दिशा इस बजट में दी है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आइये, अपनी धरती को पहचानिये, अपने संस्कार को पहचानिये, भारत के किसानों, मजदूरों को पहचानिये, भारत के पशुधन को पहचानिये। वही हमारा प्राण है और वहीं से हमारी चेतना रही है।

अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि इस देश में हमारे जितने भी पिछड़े राज्य हैं, उन पिछड़े राज्यों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? प्रणब बाबू, जो उद्योग धंधे खेती लायक भूमि पर लगेंगे, वे बंजर भूमि पर क्यों नहीं लगेंगे? वर्ष 1950 से लेकर आज तक एक करोड़ हैक्टेयर से ऊपर की खेती लायक जमीन कम हो गयी है। जब कृषि की भूमि कम होगी, उत्पादन कम होगा, अनाज कम होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। यह बड़े-बड़े लोगों का षडयंत्र है कि खेती को मारो। जब खेती में उत्पादन कम होगा, अनाज कम होगा, हाहाकार मचेगा, विदेश से आयात होगा और एक पैसे का माल तीन पैसे में खरीदेंगे, हिन्दुस्तान के किसान को गेहूं का दाम 1050 रुपये क्विंटल देंगे और बाहर से 1600 सौ रुपये क्विंटल मंगायेंगे, हमारे घर की गेहूं 1050 रुपये क्विंटल और गोरी चमड़ी वाले की गेहूं 1600 रुपये क्विंटल है, यह कहां का इंसाफ है? इसलिए मेरी आपसे

विनम्र प्रार्थना है कि आइये, एक मूल्य आयोग बनाइये। मूल्य आयोग बनाकर औद्योगिक माल और खेतिया माल के संतुलन को बनाने के लिए लागत तय करिये।

डा0लोहिया ने इसी सदन में कहा था : अन्न दाम का घटना-बढ़ना, आना सेर के अन्दर हो, डेढ़ गुने की लागत पर करखनिया माल की बिक्री हो। कारखाने में उत्पादित वस्तु की जो भी लागत हो, जैसे सीमेंट की एक बोरी अगर 100 रूपए में तैयार होती है, तो हिन्दुस्तान में वह कहीं भी डेढ़ सौ रूपए से ज्यादा में न बिके। जो दवा एक रूपए में तैयार होती है, वह कहीं भी डेढ़ रूपए से ज्यादा दाम में न बिके। जब हमारा अनाज बिकता है, 1050 रूपए प्रति क्विंटल आपने खरीद लिया। जब हम अपना अनाज बेटी की शादी, बाप के श्राद्ध या बेटे की पढ़ाई के लिए, अपने रोजी-रोजगार के लिए बेच चुकते हैं, जब वह हमारे खर्चे में निकल गया, तब बाजार में अनाज की कीमत बढ़ जाती है। वे लोग आपका साथ क्यों देंगे? किसने आपका साथ दिया है? जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, लूटा है, वे मजे में हैं, उन्होंने चुनाव में शहरों के आस-पास आपको बहुमत देकर जिताया है क्योंकि जो लूटने वाले हैं, वे मालामाल हो गए हैं। आपको वे क्यों नहीं जिताएंगे? जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के खजाने से वेतन-भत्ते पाते हैं, उनका वेतन बढ़ता है। पंचवा वेतन आयोग, छठां वेतन आयोग बनाकर उनकी जेब में आप पैसे डालते हैं, वे सरकार के खजाने से वेतन-भत्ते पाते हैं। आप उनके खर्चों को बढ़ा देते हैं। महंगाई बढ़ी एक रूपया और आप उनके पॉकेट में डाल देते हैं डेढ़ रूपए, वे तो संतुÂट हो जाते हैं। मरता कौन है? ये 60-65 प्रतिशत गांव के किसान और 82 प्रतिशत गांव में बसने वाले लोग हैं। जब गांव में हम 82 प्रतिशत हैं, तो आप हमें बजट में 82 प्रतिशत हिस्सा क्यों नहीं देंगे? जब खेती में 60-65 प्रतिशत लोग हैं, तो आप हमको बजट में 60-65 प्रतिशत हिस्सा क्यों नहीं देंगे? हम अपना हिस्सा मांगते हैं। हमारा हिस्सा आपको देना होगा। अगर नहीं देंगे तो विद्रोह होगा, केवल समाज के अन्दर नहीं, सारे राÂट्र में किसान विद्रोह होगा। इसलिए यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं चेतावनी देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह गांव की आवाज है, किसान की आवाज है, दलित की आवाज है, भूख-प्यासे लोगों की आवाज है, गांव की मिट्टी की आवाज है। मेरी आवाज को सुनिए, समझिए, इस पर आगे बढ़िए, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि न हम रहेंगे और न आप रहेंगे। न राजा रहेगा, न रानी रहेगी, यह माटी सभी की कहानी कहेगी। जब इतिहास में आपका नाम मिट जाएगा, इस संसद का इतिहास नहीं रह जाएगा, उस दिन चेतने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

प्रणब बाबू, आप उठिए, अपनी दिशा से, अपनी दÂि से एक नई दिशा इस बजट को दीजिए, गांव वालों को हिस्सा चाहिए, किसान को हिस्सा चाहिए, मजदूर को हिस्सा चाहिए, पिछड़े, दलित, वनवासी को सम्मान चाहिए। उनकी औरतों को क्या आपने कभी देखा है? वह मिट्टी में काम करती है, पसीने से लथपथ हो जाती है। पसीने के कारण उसके शरीर से बदबू आती है। गिट्टी तोड़ने वाली, सड़क पर मजदूरी करने वाली भगवती देवी कभी लोहिया के शासन में एमएलए बनी थी और संसद तक भी आई थी। क्या आप वैसी महिला को इस बजट के माध्यम से उस स्थिति से निकाल सकते हैं? राजीव गांधी ने कहा था, तुम बजट बनाओ, तुम्हारा पैसा अन्तिम मानव तक कितना पहुंचता है, उससे यह जांचना कि वह बजट कितना सफल हुआ। दीन दयाल उपाध्याय ने कहा कि अन्तिम मानव को देखो। लोहिया ने कहा समता समाज बनाओ। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा कि सत्ता, बहुमत के बल पर कभी इतराना मत, बहुमत के बल पर कभी ईसा मसीह को शूली पर लटकाया गया था। बहुमत से उनको फांसी देने वाले इतिहास से मिट गए, लेकिन ईसा मसीह का नाम अमर है। कभी मोहम्मद साहब पर ईंटें-पत्थर बरसाने वाले इतिहास से मिट गए, लेकिन मोहम्मद का नाम अमर है। महात्मा गांधी के सीने पर गोली चलाने वाले तत्व मिट जाएंगे, लेकिन इतिहास में वह अमर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर बजट में हिस्सा देना है, तो हिस्सा दीजिए, हमको समता दीजिए, समानता दीजिए, हमारे पशुओं को बचाइए, मेरी धरती को बचाइए, मेरी गंगा को बताइए, मेरी नदियों को बचाइए, मेरे जंगल को बचाइए जिससे यह देश बचेगा, यह समाज बचेगा, तब आप रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं, लेकिन वित्त मंत्री का सम्मान करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, especially from major Parties, please use your discretion. Otherwise, your own colleagues would suffer. Shri Hukmadeo Narayan Yadav has taken 23 minutes.

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Budget. As I was listening to the discussion around the House since 2.15 in the afternoon, I was struck by the criticism by certain sections of this House. It seems to suggest that we have got the Budget all wrong.

It should not be forgotten that it is only two months back that this country voted in a General Election. In that General Election, a decisive mandate was given to the UPA. There is something right that we must have done in the last five years that the people of this country decided to repose their faith in the Congress-led-UPA and gave us another five years to govern this country.

While constructive criticism is welcome, but constructive criticism should not become a platform to rubbish something which expresses and articulates the will of the nation.

At the height of the great depression in the USA on the 2nd of July 1932, Governor Roosevelt as he was then known, while accepting the American Democratic Presidential nomination, articulated his concept of a new deal. He based that new deal on a very simple moral principle. With your permission, I quote:

> "The welfare and soundness of a nation depends first upon what the great mass of people wish and need; and second, whether or not, they are getting it."

Seventy seven years later, in the midst of an unprecedented global meltdown, the Finance Minister seems to have incorporated that moral maxim at the heart of his Budget because a Budget is not merely an accounting statement. It is also a statement of the socio-economic reality of the country.

It is uncanny − the parallels are uncanny. In 1929, when the great depression took place, it was the bankers − Mr. Roosevelt called them 'money-changers', it was their greed which caused the banking system to go into a crisis and for the depression to come on. Again in 2008, it was the bankers and their exotic derivatives which caused this global economic meltdown.

In both those instances, while the bankers, the high-priests of the finance industry abdicated their responsibility, it is the wise-men who stepped in; it is the politicians and the statesmen who stepped in, in order to rescue the economy. It was Franklin Roosevelt at that point of time and it is the collective G-20 now.

It is very important that this Budget which has been presented by the Finance Minister needs to be contextualized; it needs to be put in a global perspective. In May 2009, the IMF came out with a report which said that for the first time after the Second World War, the global economy in 2009 would contract by 1.3 per cent; it is unprecedented that for the first time in 60 years, it is happening.

In the last one year or to be precise, in the last six months, Japan's exports have gone down by 44 per cent; Chinese exports have gone down by 33 per cent. The collective economies of the ASEAN countries have taken a hit by over 13 per cent. The Asian Development Bank in its report says that in the year 2009 alone, more than 62 million people in Asia would slip into poverty.

Given this global context, I think the UPA Government - and I would like to refer to it as UPA−I - needs to be complimented for its economic management. India has been able to ride out this crisis to a very great extent because of the sound macro economic management of this country which was done between the years 2004-09. There was an illusion to growth rates. I do not want to get into a confrontationist mode against the more but let me point out that between 2004 and 2009 the economy of India grew by 8.85 per cent on an average, which is a record for the last two decades. I think nobody can take away that credit from the UPA Government. On the back, there is a very robust saving to GDP ratio, a very robust investment to GDP ratio, this country has been able to build very sound macro economic fundamentals.

I was hearing the lead speaker of the BJP, the very venerable Dr. Murli Manohar Joshi eluding to the farm sector. Again, without getting confrontationist let me point out that when the NDA was in Office, in the year 2002-03, the rate of agricultural growth was negative, minus 7.2 per cent if I am not mistaken and the average growth rate of agriculture between 2004 and 2008 has been 3.55 per cent and I think that is a splendid recovery which has been made by the UPA dispensation.

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** आज आलू कितने रुपये पर बिक रहा है?...(व्यवधान)

**श्री मनीÂष तिवारी :** देखिये, हमने आपको इंट्रप्ट नहीं किया था, आप बैठ जाइये और जब हम अपना भाषण खत्म कर लें तब आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा।

The current Budget can be summed up in three short words. It is a Budget which 'cares', it is a Budget which 'shares' and it is a Budget which 'dares'. This Budget which has been presented by the Finance Minister is a very judicious mix of short-term stimulus, medium-term fiscal prudence and long-term institutional reforms. Since 2.15 p.m. in the afternoon there has been criticism from certain quarters. Let me reiterate some of the key provisions of this Budget in order to substantiate the averment that I have made earlier.

The short-term stimulus which the Finance Minister has outlined and which will go a long way in kick-starting the economy commences with the IIFCL as a route to finance infrastructure. As rightly pointed out, if the IIFCL model of private-public partnership funding works a Rs.100,000 crore worth of investment in infrastructure can be created. Similarly, the focus on highways and railways, because both of them have an employment multiplier impact, the focus on urban infrastructure, focus on a task force in order to alleviate the problems of those farmers who are indebted to private money lenders and last but not least the incentives which have been provided to the export sector will go a long way in ensuring that India comes back to the trajectory of a 9 per cent growth rate.

Similarly, in the medium-term the decision of the Finance Minister to revisit the whole question of fertiliser subsidy, a political hot potato, is a bold decision. Notwithstanding that a very bold initiative taken in the Budget is that the fertiliser subsidy issue needs to be reviewed. A fresh look at the way we price our petrol and diesel, disinvestment back on the front burner of the Government and overhaul of the income tax code which, as I can tell you as a practising lawyer, is known more for its exemptions and exceptions rather than the rules that it incorporates or the law that it incorporates and encouraging the use of bio-diesel are all steps in the medium-term which will help India achieve its goal of becoming a great power and occupying its rightful place on the high table.

Similarly, if you look at this Budget from long term point of view, there has been a lot of criticism about the NREGA around this House

and I would reply to that in only one sentence. अंगूर खट्टे हैं मेरे भाई। एनआरईजीए ने कांग्रेस को राजनीतिक फायदा नहीं दिया है, बल्कि जो गरीब है, जो गांव में बसता है, खेत-खलिहान में बसता है, मजदूर है, एनआरईजीए ने उसका ध्यान रखा है। इसका परिणाम ही आपको चुनाव में देखने को मिला है। यह बात आपको भूलनी नहीं चाहिए।

Similarly, the decisions to have a unique Identification Authority for India, investments-linked tax exemptions, that if you invest you will be entitled to tax exemptions rather than the other way around on profitability, the move towards a dual mode GST and electoral trust, all these are initiatives which over the next five years are going to pave the way for the transformation of India as some of our friends in the Left would have understood by now. Change always has to be incremental and change always has to be calibrated in a manner whereby society is able to absorb it. If you try and thrust change down the throats of the people, then exactly the same thing happens to you what happened to Soviet Union and East Europe. You open up a Pandora's box which you are not able to then control.

Finally, I would like to conclude by saying two things. The Fringe Benefit Tax has been abolished in the Budget Speech of the Finance Minister. But if you read the Explanatory Memorandum, the incidence of taxation has been shifted from the employer to the employee. I would like to request the Finance Minister to kindly review the incidence of taxation on the employees and the reason I am saying that is because in recessionary economy, the entrepreneurial spirit which can kick start the new economy which is another dimension of kick starting the new economy may get very severely impaired if this incidence of taxation remains on the employee.

Last but not least, Mr. Finance Minister, may I thank you for Rs.50 crore grant which you have given to my *alma mater*, Punjab University, Chandigarh. I would like to request you to also talk to the University to see that the new campus of that University − if at all they decide to build it − they should build it in Ludhiana because the geographical spread of the Punjab University extends beyond Chandigarh.

**श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज):** सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट चर्चा में बोलने का अवसर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2009-10 का जो सामान्य बजट प्रस्तुत किया है, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी उस अर्थव्यवस्था की गाड़ी की गति को तेज करना चाहते हैं, जिसके सारे पहिए पंक्चर हैं। बजट पेश करने के बाद मंत्री जी ने स्वयं एक गोष्ठी में कहा था कि तेज विकास दर के लिए वित्तीय घाटा जरूरी है। मैं अपनी बात को ज्यादा लम्बा नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि हमारे बोलने के लिए समय कम है, लेकिन बजट में यह स्वीकार किया गया है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। इसमें ऋण प्रसार को बढ़ाने, ऋण राहत और सिंचाई कार्यक्रम के अतिरिक्त किसी भी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से एक घोषणा की गई है कि हम उन किसानों को जो समय से अपना ऋण चुका देंगे, उनको हम 7 प्रतिशत की जगह पर 6 प्रतिशत का लाभ देंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसान अपना कर कैसे चुकाएगा? जो किसान पैदा करता है, जब तक उसे उसकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, वह अपने कर्ज को अदा नहीं कर पाएगा।

दूसरी बात, बजट के अंदर अभी हुकुम नारायण जी भाषण कर रहे थे। पशु धन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। आज हम लगातार देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थों में किस प्रकार से मिलावट हो रही है। किस प्रकार से चाहे दूध हो या घी हो, किस प्रकार से मिलावट होने का काम हो रहा है और जब दूध 12 रुपये लीटर बिकेगा और पानी 10 रुपये लीटर बिकेगा तो ऐसे में किसान कैसे सुखी हो सकता है? आज इतना नकली घी, दूध पूरे देश में आ रहा है कि जो दूध, घी और मक्खन का इस्तेमाल हम करते हैं, उसमें यह जरूर सोचते हैं कि यह नकली भी हो सकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पशु धन के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। जो केन्द्र की वित्तपोषित योजनाएं हैं, चाहे वह नरेगा हो, जिसकी बहुत वाहवाही की गई है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है कि कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि नरेगा के कारण उनको बहुत लाभ हुआ है। आप मानिए। लेकिन नरेगा की सच्चाई को भी समझने की कोशिश करिए। आज यह नरेगा जो गांव के चुने हुए प्रधान हैं, उनके गले की फांसी बनी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। विनय पांडे जी हमारे बलरामपुर लोक सभा से आते हैं। यहीं पर बैठे हुए हैं। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि आज यू.पी. के वे अधिकारी जिन गांवों में मौजूदा सरकार चुनाव हार गई है, उन गांवों के प्रधानों की ग्राम कार्य योजना भी बनाने को तैयार नहीं हैं। हमारे पुनिया साहब बैठे हैं। वे भी इस हकीकत को जानते हैं। जो नरेगा की योजना के बारे में सारे विपक्ष के लोगों ने बताया है कि यह फ्लॉप है। मैं नहीं कहता कि यह फ्लॉप है। अगर यह योजना फ्लॉप हुई है तो मैं कहूंगा कि जो जगह-जगह पर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके कारण यह योजना फ्लॉप हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी मंशा में कोई संदेह नहीं है। बीपीएल कार्ड में जिस प्रकार से धांधली है और सदन में कई वक्ताओं ने बीपीएल कार्ड में बरती गई अनियमितताओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि केवल यू.पी. में ही नहीं, सारे देश के अंदर बीपीएल कार्ड किनको मिला है और किनको मिलना चाहिए, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, तभी आपका उद्देश्य जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का है, वह पूरा हो सकेगा, नहीं तो आपकी योजना सफल नहीं हो सकेगी।

आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार अगर कहीं देखना है, तो इसके कारण देखा जा सकता है। आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण जो आप चावल, तेल और चीनी जिन लोगों को देना चाहते हैं, उन लोगों तक न पहुंचकर आज यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। आज इस बात की जरुरत है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विशेष ध्यान सरकार का होना चाहिए।